

(केवल सरकारी प्रयोग हेतु)



# वार्षिक सामान्य प्रशासनिक रिपोर्ट

## 2016-2017

योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार  
शिमला-171002

## विषय सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ
1.	पृष्ठभूमि एवं परिचय	1
2.	योजना विभाग-स्टाफ स्थिति	1-2
3.	संगठनात्मक ढांचा	2
3.1.	राज्य योजना बोर्ड	2-4
3.2.	मुख्यालय	4
	(I) प्रशासन प्रभाग	4-5
	(II) योजना प्रारूपण प्रभाग	5-6
	(III) योजना कार्यान्वयन	6-8
	(IV) पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	8-9
	(V) क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन प्रभाग	10-15
	(VI) जन शक्ति एवं रोजगार प्रभाग	15
	(VII) बाह्य सहायता परियोजना/ नवाचार प्रभाग	16-20
	(VIII) कौशल विकास प्रभाग	20-21
	(IX) नाबार्ड-ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि प्रभाग	21-24
	(X) 20-सूत्रीय कार्यक्रम प्रभाग	24-28
	(XI) रेलवे प्रभाग	29
	(XII) मूल्यांकन प्रभाग	30
	(XIII) विधायक प्राथमिकता योजना प्रभाग	30-31
	(XIV) कम्प्यूटर प्रभाग	31-32
3.3.	जिला कार्यालय	32-33
4.	सूचना का अधिकार नियम 2005	34-40

## 1. पृष्ठभूमि एवं परिचय

योजना विभाग का दायित्व योजना प्राथमिकताओं एवं सकल योजना परिव्यय को निर्धारित करना, विभिन्न घटकों / सेवाओं के लिए धनराशि चिन्हांकित करना तथा पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं को तैयार करना है। इसके अतिरिक्त योजनाओं/परियोजनाओं का मूल्यांकन एवं अध्ययन करना, विकेन्द्रीकृत नीति को बढ़ावा देना, योजना स्कीमों की नियमित समीक्षा, बाह्य-सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विश्लेषण और नाबार्ड से निधि प्राप्त आर.आई.डी.एफ. योजनाओं का कार्यान्वयन आदि कार्य योजना विभाग द्वारा किये जा रहे हैं। योजना विभाग द्वारा जन-शक्ति एवं रोजगार सृजन, पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना, 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा, प्रदेश में रेल विस्तार, इत्यादि का कार्य भी किया जा रहा है।

## 2. योजना विभाग-स्टाफ स्थिति

क्र० सं०	पद नाम	स्वीकृत पद	भरे गए पद	रिक्त पद
1.	2.	3.	4.	5.
1.	अध्यक्ष, रोजगार सृजन एवं संसाधन	1	1	0
2.	अध्यक्ष, 20-सूत्रीय कार्यक्रम	1	1	0
3.	उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड	1	1	0
4.	सलाहकार (योजना)	1	1	0
5.	संयुक्त निदेशक	1	1	0
6.	उप-निदेशक	6	6	0
7.	अनुसंधान अधिकारी/जिला योजना अधिकारी	20	19	1
8.	साख योजना अधिकारी	10	10	0
9.	सहायक अनुसंधान अधिकारी	17	13	4
10.	सांख्यिकीय सहायक	21	11	10
11.	गणक	6	4	2
12.	सिस्टम एनालिस्ट	1	0	1
13.	प्रोग्रामर	1	1	0
14.	कार्यक्रम योजना अधिकारी	2	2	0
15.	गणक संचालक	1	0	1
16.	निजी सचिव	1	1	0
17.	निजी सहायक	2	1	1
18.	वरिष्ठ आशुलिपिक	1	1	0
19.	कनिष्ठ आशुलिपिक	6	6	0
20.	आशुटंकक	3	3	0
21.	कनिष्ठ कार्यालय सहायक	11	0	11
22.	अधीक्षक श्रेणी-I	1	1	0
23.	अधीक्षक श्रेणी-II	1	1	0
24.	वरिष्ठ सहायक	17	17	0
25.	कनिष्ठ सहायक	1	1	0

1.	2.	3.	4.	5.
26.	लिपिक	13	10	3
27.	प्रतिलिपि यन्त्र चालक	1	1	0
28.	चालक	5	5	0
29.	चपड़ासी	20	19	1
30.	चौकीदार	1	0	1
31.	फ्राश	1	1	0
32.	जमादार	1	1	0
33.	सफाई कर्मचारी	1	1	0
	<b>कुल</b>	<b>177</b>	<b>142</b>	<b>35</b>

\* : राज्य योजना बोर्ड तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्षों के वेतन व भत्तों के बारे में सरकार द्वारा उनके मनोनीत होने के समय पर निर्णय लिया जाता है ।

### 3. संगठनात्मक ढांचा

योजना विभाग के संगठनात्मक ढांचे का विवरण निम्न है:-

1. राज्य योजना बोर्ड ।
2. मुख्यालय
3. जिला कार्यालय ।

#### 3.1. राज्य योजना बोर्ड:

सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्यों को मनोनीत करके राज्य योजना बोर्ड का गठन प्रदेश सरकार द्वारा 12 फरवरी, 2013 को किया गया ।

#### I. राज्य योजना बोर्ड की संरचना:

- (i) अध्यक्ष-माननीय मुख्यमंत्री
- (ii) गैर-सरकारी सदस्य

1. समस्त केबिनेट मंत्री, हिमाचल प्रदेश ।
2. हिमाचल प्रदेश से सम्बन्धित समस्त सांसद (लोक सभा एवं राज्य सभा) - अलग से अधिसूचित ।
3. किसान, उद्योग एवं व्यापार, अनुसूचित जाति, जन-जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के एक-एक प्रतिनिधि - अलग से अधिसूचित ।
4. भूतपूर्व सांसद/विधायक एवं वर्तमान विधायक - अलग से अधिसूचित ।
5. सेवानिवृत्त मुख्य सचिव/सरकारी अधिकारी-अलग से अधिसूचित ।

(iii) **सरकारी सदस्य**

1. मुख्य सचिव
2. समस्त प्रशासनिक सचिव
3. हिमाचल प्रदेश में समस्त सरकारी विश्वविद्यालयों के उप-कुलपति

(iv) **पदेन सदस्य (Ex Officio)**

1. अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज
2. सी.जी.एम. नाबार्ड, शिमला

(v) **सदस्य सचिव : सलाहकार (योजना)**

II. **नियुक्ति की शर्तें:** सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाती हैं ।

III. **योजना बोर्ड मुख्यालय:** योजना बोर्ड का मुख्यालय शिमला है परन्तु इसकी बैठकें किसी भी स्थान पर अध्यक्ष की अनुमति से की जा सकती हैं ।

IV. **योजना बोर्ड के कार्य:**

- राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप प्रदेश की योजना प्राथमिकताओं का निर्धारण ।
- वित्तीय संसाधनों एवं जन-शक्ति की संगठनात्मक एवं संस्थापक योग्यताओं का आकलन ।
- प्रदेश में महत्वपूर्ण सैक्टर, जिलों, क्षेत्रों इत्यादि में विकास का आकलन ।
- प्रदेश के सीमित संसाधनों के इष्टतम उपयोग हेतु योजना तैयार करना, राज्य सरकार की वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने में सहायता करना तथा विभिन्न क्षेत्रों में विकास आकलन करना ताकि राज्य के सामाजिक, आर्थिक विकास की अधिकतम सीमा प्राप्त की जा सके ।
- राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में आने वाली बाधाओं कारणों की पहचान तथा राज्य की योजनाओं का सफलतापूर्वक कार्यन्वयन का निर्धारण ।
- प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान विकासात्मक असंतुलनों को दूर करने के लिए नीति निर्धारण तथा जिला एवं क्षेत्रीय योजनाओं के प्रारूपीकरण में सहायता करना ।
- योजना कार्यन्वयन की सामयिक समीक्षा तथा प्रदेश की नीति एवं कार्यक्रमों में सुधार के सुझाव ।
- चालू कार्यक्रमों की विवेचनात्मक समीक्षा तथा कार्यक्रमों के निरन्तरीकरण का सुझाव ।
- बेराजगारी की समस्या के निदान के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सलाह देना ।

- सरकार द्वारा बोर्ड को प्रेषित आर्थिक विकास के मामलों पर सलाह देना ।
- वर्तमान आर्थिक स्थिति एवं नीतियों का विश्लेषण करना और प्रदेश के विकास के लिए विकासात्मक कार्यक्रमों के उपयुक्त कार्यन्वयन एवं सुधार के सम्बन्ध में उचित सुझाव देना ।
- योजना कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचना का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण करना ।
- सरकारी निगमों एवं बोर्डों की कार्य प्रणाली का परीक्षण तथा उनमें सुधार लाने के सुझाव देना ।
- जिला स्तर पर योजना स्कीमों के कार्यन्वयन में आने वाली कठिनाईयों का पता लगाना तथा इन कठिनाईयों के निराकरण एवं समाधान के उपाय सुझाना ।
- अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार विभिन्न कार्यक्रमों एवं निगमों का मूल्यांकन करना ।

वर्ष 2016-17 के लिए मु0 5200.00 करोड़ रु0 के आकार को अनुमोदित किया गया था ।

### 3.2. मुख्यालय:

सरकारी नियमावली के अनुसार सरकारी कार्यों के निष्पादन हेतु योजना विभाग निम्नलिखित ढांचे के अनुसार कार्य कर रहा है :-

1.	सम्बन्धित मंत्री	माननीय मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-2.
2.	प्रशासनिक सचिव	अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
3.	विभागाध्यक्ष	सलाहकार (योजना) हिमाचल प्रदेश, शिमला-2

सलाहकार (योजना), विभागाध्यक्ष हैं । योजना विभाग में विभिन्न प्रभाग जैसे कि योजना प्रारूपण, परियोजना प्रारूपण, योजना कार्यन्वयन, कम्प्यूटरीकरण, मूल्यांकन, जनशक्ति एवं रोजगार, प्रशासन, क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन, पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना, रेलवे, 20-सूत्रीय कार्यक्रम तथा आर.आई.डी.एफ. कार्य कर रहे हैं । ये प्रभाग संयुक्त निदेशक/ उप-निदेशकों के नियन्त्रण में कार्य कर रहे हैं । संयुक्त निदेशक सलाहकार (योजना) के नियंत्रण में कार्य करते हैं तथा कार्य निष्पादन के लिए सलाहकार (योजना) का सहयोग करते हैं । संयुक्त निदेशक कार्यालय अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं । प्रभागानुसार उद्देश्य, कार्यक्रम, आबंटन, व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है:-

#### I. प्रशासन प्रभाग:

संयुक्त निदेशक का पद दिनांक 31 अगस्त, 2012 को पदोन्नति से भरा गया है । संयुक्त निदेशक, (योजना) को विभाग में कार्यालय

अध्यक्ष घोषित किया गया हैं । प्रशासन प्रभाग संयुक्त निदेशक की अध्यक्षता में कार्य करता है ।

यह प्रभाग योजना विभाग की प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार कार्य करता है । प्रभाग के मुख्य कार्य जैसे कि रिक्त पदों का भरना, पदोन्नति, स्थानांतरण, अधिकारियों / कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, स्थाईकरण, भण्डार, स्थापना, बजट, लेखा आपत्ति, पीएसी, सीएजी, व अन्य विविध कार्य जो प्रभाग को सौंपे गए हैं, किये जा रहे हैं। वर्ष के दौरान प्रभाग द्वारा उपरोक्त वर्णित कार्य निष्पादित किए गए हैं ।

## II. योजना प्रारूपण प्रभाग:

### 1. राज्य की वार्षिक योजना (2017-18) का प्रारूपीकरण :

वार्षिक योजना (2017-18) के प्रारूपीकरण हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) की अध्यक्षता में सभी सम्बन्धित विभागों के साथ योजना प्राथमिकताओं के निर्धारण हेतु चर्चा के लिए अक्टूबर, 2016 में शृंखलावार बैठकों का आयोजन किया गया ।

वार्षिक योजना (2017-2018) के प्रारूपीकरण हेतु सभी सम्बन्धित विभागों/एजेंसियों को दिशा-निर्देश जारी किए गये जिसके माध्यम से उन्हें अपने विभाग से सम्बन्धित विस्तृत योजना प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया ।

विभागीय प्रस्तावों की जांच पड़ताल करने तथा प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात वार्षिक योजना (2017-2018) का आकार 5700 करोड़ रुपये प्रस्तावित कर ड्रॉफ्ट प्रारूप तैयार करके राज्य योजना बोर्ड की दिनांक 6 फरवरी, 2017 को हुई बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया , जिसे राज्य विधानसभा द्वारा भी पारित कर दिया गया । सैक्टरवार विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

(रु0करोड़ों में)

क्रम संख्या	सैक्टर	वार्षिक योजना (2017-18) का प्रस्तावित परिव्यय
1.	2.	3.
1.	कृषि एवं सम्बन्धित सेवाएं	713.66
2.	ग्रामीण विकास	113.88
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	27.78
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	371.30
5.	ऊर्जा	682.70
6.	उद्योग एवं खनन	118.96
7.	संचार एवं परिवहन	1073.52
8.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	17.37
9.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	267.35
10.	सामाजिक सेवाएं	2213.16
11.	सामान्य सेवाएं	100.32
	<b>कुल</b>	<b>5700.00</b>

- वार्षिक योजना 2017-18 का प्रारूपीकरण विश्वव्यापी तथा राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्यों को मध्यनजर रखते हुए किया गया ।
- 3 वर्षीय कार्य योजना, 7 वर्षीय रणनीति व 15 वर्षीय विजन दस्तावेज के प्रारूपीकरण हेतु प्रारम्भिक कार्य नीति आयोग के निर्देशानुसार सतत विकास लक्ष्यों को मध्यनजर रखते हुए किया गया ।
- राष्ट्रीयस्तर पर नीति आयोग द्वारा बनाई गई क्षेत्रीय नीतियों/सुझावों के अनुसार कार्य करने हेतु विभिन्न विभागों व नीति आयोग से समन्वय स्थापित किया गया ।

### III. योजना कार्यान्वयन प्रभाग:

विधान सभा में बजट पारित होने के उपरान्त, योजना बजट का कार्यान्वयन निम्न ढंग से शुरू होता है:-

1. यह प्रभाग विभिन्न विभागों से प्राप्त विचलन और पुनर्विनियोजन प्रस्तावों का विस्तृत परीक्षण करता है। आवश्यकता व प्राथमिकता को मद्देनजर रखते हुए ही विचलन या पुनर्विनियोजन की अनुमति दी जाती है।
2. आधिक्य प्रस्तावों को किसी अन्य मद जिसमें व्यय की संभावनायें कम हों या कोई परियोजना जिसकी चालू वर्ष में क्रियान्वयन की संभावना न हो तथा सरकार की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुये उसमें से कटौती करके पूरा किया जाता है।
3. आधिक्य प्रस्तावों को तत्काल निपटाने के लिये विभागों के साथ बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।
4. इस अवधि में सभी सम्बन्धित विभागों से उनके प्रशासनिक विभागों के माध्यम से पुनर्विनियोजन के प्रस्ताव चिन्हांकित व गैर चिन्हांकित मदों में जांच और परीक्षण के लिये आमंत्रित किये गए।
5. इस अवधि में 527 मामले विभिन्न विभागों से प्रशासनिक विभागों के माध्यम से परामर्श हेतु योजना कार्यान्वयन प्रभाग में प्राप्त हुए, इनका परीक्षण किया गया तथा सक्षम प्राधिकारियों के पूर्व अनुमोदनोपरान्त प्राप्त करने के उपरान्त उचित परामर्श सम्बन्धित विभागों को दिया गया।
6. बजट के अनुरूप योजना कार्यान्वयन निर्विघ्न करने के लिये सम्पूर्ण वार्षिक योजना को सॉफ्टवेयर के माध्यम से बजट से जोड़ा गया है।



उपरोक्त के अतिरिक्त, योजना कार्यन्वयन प्रभाग द्वारा इस अवधि के दौरान निम्न गतिविधियां भी की गई :-

#### 1. त्रैमासिक बजट आबंटन

वर्ष 2016-17 में सामान्य योजना परिव्यय के अन्तर्गत सभी विभागों को त्रैमासिक बजट प्राधिकृत किया गया तथा वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों को एकत्रित व समेकित किया गया।

योजना व्यय के लिये निम्न मापदंडों को निर्धारित किया गया है :-

तिमाही	योजना व्यय (%)
प्रथम	20%
द्वितीय	25%
तृतीय	30%
चतुर्थ	25%
योग	100%

#### 2. बजट आश्वासन

इस प्रभाग द्वारा वर्ष 2016-17 के बजट भाषण में दिये गए बजट आश्वासनों की प्रगति की समीक्षा की गई। सभी कार्यन्वयन विभागों से सूचना एकत्रित व समेकित की गई।

#### 3. भारत सरकार के साथ लम्बित मामले

‘भारत सरकार के साथ लम्बित मामले’ आवश्यक मुद्दों/मामलों का संकलन है जो भारत सरकार के साथ लम्बित पड़े हैं। कैबिनेट सचिवालय द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पर प्रमुख मामलों को अपलोड किया गया है जिनकी ई-समीक्षा के माध्यम से निरन्तर समीक्षा की जा रही है।

#### 4. केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का प्रदेश की आर्थिकी में विशेष स्थान है क्योंकि यह प्रदेश के स्त्रोतों का अनुपूरण करती हैं। वर्तमान में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें या तो शत प्रतिशत या केन्द्र और राज्य में विभिन्न अनुपातों में चल रही हैं। इस प्रभाग ने कार्यन्वयन विभागों को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के वित्तीय निहितार्थ और समकक्ष योजना में राज्य प्रावधानों पर परामर्श दिये हैं।

#### 5. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

स्वतन्त्र एजेंसियों द्वारा एच.डी.बी.आई. परियोजना की कार्य योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार चार अध्ययनों पर कार्य किया गया:-

1. हिमाचल प्रदेश में हरित विकास एवं समावेश हेतु मानव विकास अध्ययन विशेषज्ञ को समीक्षा हेतु भेजा गया।
2. 0-6 वर्ष आयु समुह के गिरते लिंग अनुपात के कारणों पर अध्ययन को अन्तिम रूप दिया गया।

3. हिमाचल प्रदेश में मानव विकास पर वित्तीय रिपोर्ट कार्ड विशेषज्ञ से टिप्पणियां प्राप्त करने के उपरान्त संशोधन के लिये भेजा गया है।
4. हिमाचल प्रदेश में गुज्जरों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के आकलन हेतु अध्ययन पर विशेषज्ञ की टिप्पणियां एवं सुझावों को शामिल करने के बाद अन्तिम रूप दिया गया।

#### IV. पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना प्रभाग:

प्रदेश सरकार द्वारा क्षेत्रीय विषमताओं की पहचान एवं उनको दूर करने के लिए पिछड़ा क्षेत्र उप योजना शुरू की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए एक व्यापक नीति 1995-96 से हिमाचल प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही है। पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना से सम्बन्धित नीति में सरकार के निर्णयानुसार समय-समय पर आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। नीति की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं:-

(क) पिछड़ा क्षेत्र उप योजना में पिछड़ा घोषित क्षेत्रों को निम्न तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:-

- (i) **पिछड़े घोषित विकास खण्ड** : ऐसे सभी विकास खण्ड जिनमें 50 प्रतिशत या इससे अधिक पंचायतें पिछड़ी घोषित हों, पिछड़े विकास खण्ड घोषित किए गए हैं। प्रदेश में कुल आठ विकास खण्ड पिछड़े घोषित हैं जिनमें कुल 304 पिछड़ी पंचायतें आती हैं।
- (ii) **कंटीगुअस (Contiguous) पंचायतें** : ऐसी सभी पांच या पांच से अधिक पिछड़ी घोषित पंचायतें जिनके भौगोलिक क्षेत्र एक दूसरे से मिलते हों को पिछड़ी पंचायतों का समूह घोषित किया गया। प्रदेश में कुल 15 पिछड़ी पंचायतों के समूह घोषित हैं जिनमें कुल 133 पिछड़ी पंचायतें आती हैं।
- (iii) **बिखरी पंचायतें**: जिन पिछड़ी घोषित पंचायतों का भौगोलिक क्षेत्र एक दूसरी पिछड़ी पंचायत से नहीं लगता हो अथवा पिछड़ी पंचायतों का समूह पांच पंचायतों से कम हो ऐसी पंचायतों को बिखरी पंचायतें घोषित किया गया। प्रदेश में कुल 110 बिखरी हुई पिछड़ी पंचायतें हैं।

(ख) चयनित 13 विकास शीर्षों में पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के लिए परिव्यय चिह्नंकित किया जाता है।

(ग) लाभार्थी एवं क्षेत्र मूलक, दोनों प्रकार की, योजनाओं को अपनाया गया है।

(घ) जिलों को पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत बजट आवंटन, जिले में विद्यमान कुल पिछड़ी पंचायतों के अनुपात में किया जाता है।

(ड) उप योजना का प्रबन्धन, जिला योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति के अनुमोदन पश्चात, उपायुक्तों के माध्यम से किया जाता है । उपायुक्तों एवं जिला योजना अधिकारियों को इस उप-योजना का क्रमशः नियंत्रण तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित किया गया है ।

(च) योजना विभाग पिछड़ा क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत केवल पूंजीगत शीर्षों को ही नियन्त्रित करता है । राजस्व शीर्षों का संचालन सम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाता है ।

प्रदेश में कुल 3226 पंचायतों में से 547 पंचायतें पिछड़ी घोषित की जा चुकी हैं । सरकार द्वारा उप-योजना के लिए अलग बजट की व्यवस्था मांग संख्या-15 (योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना) में की जाती है । वर्ष 2016-17 के लिए मु0 49.50 करोड़ रु0 का बजट प्रावधान योजना में पूंजीगत कार्यों के लिए रखा गया था और वर्ष 2017-18 के लिए पूंजीगत कार्यों के लिए मु0 54.47 करोड़ रु0 का बजट प्रावधान योजना में रखा गया है।

जिलावार पिछड़ी पंचायतों की संख्या तथा वर्ष 2016-17 के लिए पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के लिए पूंजीगत परिव्यय/व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है:-

(रु0 लाखों में)

क्रम संख्या	जिला	पिछड़ी घोषित पंचायतों की संख्या	पिछड़ा क्षेत्र उप योजना 2016-17 परिव्यय/व्यय (पूंजीगत)	
			योजना परिव्यय	अनुमानित व्यय
1.	2.	3.	4.	5.
1.	बिलासपुर	15	135.81	135.81
2.	चम्बा	159	1439.51	1439.51
3.	हमीरपुर	13	117.69	117.69
4.	काँगड़ा	17	153.91	153.91
5.	कुल्लू	79	715.22	715.22
6.	मण्डी	149	1348.98	1348.98
7.	शिमला	83	751.44	751.44
8.	सिरमौर	26	233.12	233.12
9.	सोलन	3	27.16	27.16
10.	ऊना	3	27.16	27.16
	<b>योग</b>	<b>547</b>	<b>4950.00</b>	<b>4950.00</b>

## V. क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन प्रभाग :

राज्य स्तर पर योजना विभाग में विभिन्न विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रमों के संचालन तथा अनुश्रवण के लिए क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन प्रभाग की स्थापना की गई है। विभिन्न विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार से है :-

### 1. विकास में जन सहयोग कार्यक्रम :

आधारभूत स्तर पर आधारिक संरचना के रूप में विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों की प्रभावी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने तथा सरकार के प्रयासों / स्रोतों को सुदृढ़ करने के लिए विकास में जन सहयोग कार्यक्रम को 1991-92 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लोगों की भागीदारी स्वैच्छिक रूप में व अग्रिम नकद भागीदारी द्वारा है जिसको सम्बन्धित उपायुक्त के नाम बैंक / डाकघर में खोले गए खातों में जमा करवानी पड़ती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 19.63 करोड़ रुपए की धनराशि का बजट प्रावधान रखा गया है।

**इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्न है:-**

1. शहरी क्षेत्रों में, सामुदायिक और सरकारी अंशदान की लागत भागीदारी 50:50 है, जबकि सरकारी परिसम्पतियां जैसे स्कूल भवन, स्वास्थ्य संस्थान एवं पशु चिकित्सा संस्थान, पेयजल आपूर्ति व सीवरेज योजनाओं का निर्माण और हैण्डपम्प स्थापित करने के लिए लागत भागीदारी 25:75 है, लेकिन इस सुविधा का प्रयोग समुदाय के लिए होगा न की किसी परिवार अथवा व्यक्ति विशेष के लिए।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में, समुदाय और सरकारी अंशदान की लागत भागीदारी 25:75 है, परन्तु जनजातीय क्षेत्रों, पिछड़ा घोषित पंचायतों और मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा बसे क्षेत्रों में समुदायक और सरकारी लागत भागीदारी 15:85 है।
3. कोई व्यक्ति सार्वजनिक सम्पति, कार्य की लागत का 50% हिस्सा देकर निर्माण करवा सकता है जो विशुद्ध रूप से परोपकारी रूप में हो या अपने पूर्वजों के पुण्यस्मरण के लिए हो।
4. स्वीकृत कार्यों का निर्माण स्वीकृति के एक वर्ष के अन्तराल में पूर्ण करना पड़ता है।
5. जिन परिसम्पतियों का रखरखाव करना होता है उनके रखरखाव के लिए समुदाय और सरकार कार्य की कुल लागत का 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि देने के लिए प्रतिबद्ध है।
6. सभी कार्य जिनकी अनुमानित लागत 5.00 लाख रुपए से अधिक है का निर्माण सरकारी विभागों द्वारा किया जाता है न की सोसाईटियों / स्थानीय समितियों द्वारा।

7. 5.00 लाख रुपए तक के कार्यों का कार्यन्वयन ग्रामीण विकास विभाग के सहायक/ कनिष्ठ अभियन्ता की देख रेख में किया जाना सुनिश्चित किया जाता है और प्रत्येक कार्य के नपाई उस क्षेत्र के कनिष्ठ अभियन्ता / तकनीकी सहायक की माप-पुस्तक (measurement book) में किया जाता है।

**इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न प्रकार की परियोजनाएं/ परिसम्पत्तियां स्वीकृत की जा सकती हैं:-**

1. सरकारी शिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण।
2. बहुउद्देशीय सामुदायिक/ सार्वजनिक परिसम्पत्तियों का निर्माण।
3. मोटर योग्य सड़कों एवं रज्जू मार्गों का निर्माण।
4. सिंचाई योजनाओं / पेयजल स्कीमों का निर्माण/ हैंड पम्पों की स्थापना।
5. सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के भवनों का निर्माण।
6. महत्वपूर्ण मिसिंग लिंक्स का प्रावधान जैसे कि तीन फेज की बिजली की लाइनें, एक्सरे प्लांट और रोगी वाहन इत्यादि।
7. आवारा जानवरों के लिए गो- सदन की स्थापना।

## **2. क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत नियोजन :**

विकेन्द्रीकृत योजना का कार्यन्वयन वर्ष 1993-94 से प्रदेश में आरम्भ किया गया था। अन्तर क्षेत्रीय सन्तुलित विकास बनाए रखने के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार योजना विभाग द्वारा जिलों को स्वीकृत बजट से धनराशि का आबंटन वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 60 प्रतिशत जिला की जनसंख्या तथा 40 प्रतिशत जिला के भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानीय आवश्यकता की स्कीमों व बजट में महत्वपूर्ण मिसिंग लिंक्स इत्यादि का कार्यन्वयन किया जाता है। वित्तिय वर्ष 2017-18 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 55.07 करोड़ रुपए की धनराशि का बजट प्रावधान रखा गया है।

**विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं:-**

1. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कीमों की स्वीकृति जिला स्तरीय योजना, विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति के पूर्व अनुमोदन के पश्चात ही की जाती है।
2. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल ऐसे कार्यों पर ही विचार किया जाना चाहिए जिनके प्राक्कलन तथा डिजाईन तकनीकी रूप से तकनीकी प्राधिकारी / अर्ध सरकारी / सरकारी उपक्रमों में तकनीकी शक्तियों के दायरे में किया हो। सरकारी कर्मियों/तकनीकी अधिकारी जो तकनीकी रूप से प्राक्कलनों को अनुमोदित कर सकता है वह ही कार्य का आकलन और भुगतान के संवितरण को प्राधिकृत करने में सक्षम है।

3. उपायुक्त स्थानीय जिला नियोजन के अन्तर्गत योजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां प्रदान करने में पूर्णतः सक्षम है। बशर्ते कि चयनित विकास मदों और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए बजट प्रावधान हो।
4. इस योजना के अन्तर्गत न ही किसी भी प्रकार के आवर्ती व्यय/ दायित्व और न ही स्वीकृतियाँ को इकट्ठा व किसी कार्य को वित्तीय वर्ष से अधिक चरणवद्ध करना स्वीकार्य है।
5. स्थानीय जिला नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाने वाले कार्यों को समुदाय को लाभान्वित करना चाहिए जिसमें कम से कम पाँच परिवार होने चाहिए। कोई भी कार्य व्यक्ति विशेष / एकल परिवार को लाभान्वित करता हो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं किया जाता है।
6. स्थानीय जिला नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्हीं कार्यों को स्वीकृत किया जाता है जिनका निर्माण एक ही वित्तीय वर्ष या स्वीकृति से एक वर्ष के अन्तराल में किया जाना होता है।

### 3. विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना:

प्रदेश सरकार ने विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 1999-2000 से विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना शुरू की है। इस योजना को वर्ष 2001-02 में बन्द कर दिया था परन्तु वर्ष 2003-04 में 24.00 लाख रु० बजट प्रावधान प्रति निर्वाचन क्षेत्र के साथ आरम्भ कर दिया है। प्रदेश सरकार वर्षानुवर्ष इस योजना के अन्तर्गत बजट प्रावधान बढ़ा रही है वित्तीय वर्ष 2016-17 में 1.00 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रति निर्वाचन क्षेत्रवार किया गया था। जिसे वित्तीय वर्ष 2017-18 में बढ़ाकर 1.10 करोड़ रुपये प्रति निर्वाचन क्षेत्रवार कर दिया गया है।

इस स्कीम का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण माननीय विधायकों की प्रत्यक्ष और सक्रिय भागीदारी के साथ किया जाता है। इस योजना से सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास को सुनिश्चित किया है। वर्ष 2017-18 में इस योजना के लिए 74.80 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा है।

**विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य किए जा सकते हैं:-**

1. विभिन्न पाठशालाओं में कमरों का निर्माण।
2. आयुर्वेदिक औषधालयों, पशु चिकित्सा औषधालयों व स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण।
3. हैंड पम्पों की स्थापना।
4. ऐसे गावों के लिये मोटर योग्य अथवा जीप योग्य लिंक सड़कों का निर्माण जो पहले से सड़कों से न जुड़े हुए हों।

5. गांवों में सामान्य सामुदायिक भवनों का निर्माण जो कि गांव स्तर पर विभिन्न संस्थाओं अथवा प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जा सकें।
6. स्वास्थ्य संस्थानों में ऐसे उपकरणों का प्रावधान जो वहां पहले से विद्यमान न हों जैसे कि एकसरे मशीनें, अल्ट्रासाउंड मशीनें, ई. सी.जी. मशीनें इत्यादि।
7. स्वास्थ्य संस्थानों के लिए एम्बूलेंस का क्रय बशर्ते कि उस पर होने वाले आवर्ती व्यय के लिए संबंधित संस्था/विभाग के पास पूर्ण व्यवस्था उपलब्ध हो।
8. ग्रामीण सड़कों के लिए छोटे पुलों अथवा पुलियों का निर्माण, विभिन्न खड्डों, नदी-नालों इत्यादि पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए Foot Bridges का निर्माण।
9. ग्रामीण रास्ते केवल पक्के concrete based or black topped तथा जिसमें दो पहिया वाहन चल सकें।
10. छूटी हुई बस्तियों के लिए पेय जल योजनायें जहां अतिरिक्त पाईप लगा कर सार्वजनिक नल लगाए जाने की आवश्यकता हो।
11. स्थानीय स्तर की सिंचाई स्कीमें।
12. पाठशालाओं में शौचालयों के निर्माण के अतिरिक्त बस अड्डा आदि स्थानों पर सार्वजनिक शौचालयों और स्नानगृहों का निर्माण भी करवाया जा सकता है।
13. दूर-दराज व ग्रामीण क्षेत्रों में बचे हुए घरों का विद्युतिकरण (LT Extensions).
14. स्कूल भवनों की मुरम्मत तथा स्कूल के खेल मैदानों का निर्माण कार्य।
15. पंचायतों तथा शहरी निकायों में व्यायामशाला के निर्माण का कार्य।
16. बस स्टैण्डों का निर्माण व रख-रखाव।
17. ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों में सरकारी भवनों की मुरम्मत जैसे कि सरकारी आयुर्वेदिक औषधालयों, पशु चिकित्सा औषधालयों, स्वास्थ्य संस्थान, सामुदायिक भवन, शैक्षणिक संस्थान इत्यादि।
18. ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सड़कों की मुरम्मत व रख-रखाव।
19. सामुदायिक WiFi लगाने का प्रावधान (Non-recurring expenditure).
20. निर्माण कार्यों के साथ-साथ-अन्य लोक कल्याणकारी योजनाएँ जैसे कि स्कूलों में बच्चों के बैठने का सामान, स्कूलों में खेल सामग्री, अस्पतालों में बिस्तर तथा कम्बल, जल वितरण में मोटर पम्पों को बदलना, महिला मण्डलों को बर्तन(अधिकतम 20,000/-रुपये प्रति महिला मण्डल) तथा फर्नीचर क्रय आदि भी किया जा सकता है।

#### 4. मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना:

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को नजदीकी मोटर योग्य सड़को से जोड़ने के उद्देश्य से कच्चे रास्तों को पक्का किया जाता है। इसके अतिरिक्त दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सभी मौसम में कनैक्टिविटी प्रदान करने के लिए पुलियों / पुलों का भी निर्माण करना। प्रदेश सरकार ने पहाड़ी और मुश्किल भौगोलिक क्षेत्रों के मध्यनजर 2 कि०मी० तक जीप योग्य /

ट्रैक्टर योग्य सम्पर्क मार्गों के निर्माण की अनुमति दी है। मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना 10 गैर जनजातीय जिलों के लिए वर्ष 2003-04 में आरम्भ की है। वर्ष 2004-05 में इस योजना को बन्द कर दिया था और वर्ष 2008-09 में पुनः शुरू किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत 10 गैर जनजातीय जिलों के लिए वर्ष 2016-17 और 2017-18 में 5.50 करोड़ रु० का बजट प्रावधान किया है।

#### **इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं:-**

1. इस योजना के अन्तर्गत बजट धनराशि का आंबटन योजना विभाग द्वारा उपायुक्तों को जिले की वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार कुल ग्रामीण जनसंख्या तथा जिले में आबाद गांवों की संख्या में 50:50 के अनुपात पर किया जाता है।
2. इस योजना के माध्यम से किसी प्रकार के भी आवर्ती राजस्व व्यय के लिए प्रावधान नहीं किए जाएंगे और न ही कच्चे रास्तों के निर्माण के लिए कोई स्वीकृतियां मान्य होंगी।
3. इस योजना के अन्तर्गत निर्मित पक्के सम्पर्क रास्तों का रख-रखाव सम्बन्धित पंचायत अपन स्रोत/ राजस्व से करेंगे। इस प्रकार का अनुबन्ध स्वीकृति प्रदान करने से पहले सम्बन्धित ग्राम पंचायत से लेना आवश्यक होगा।
4. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्य के तकनीकी अनुमानों का अनुमोदन ग्रामीण विकास विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता / सहायक अभियन्ता/ अधिशासी अभियन्ता निर्धारित तकनीकी शक्तियों के अनुसार करेंगे।
5. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित कार्यों को जिला स्तरीय योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति में अनुमोदित करवाना आवश्यक है।
6. इस योजना के अन्तर्गत निर्मित किए जाने वाले पक्के रास्तों का कार्यान्वयन स्वीकृत धनराशि के अन्दर ही होगा। इस योजना के अन्तर्गत संशोधित स्वीकृति का कोई प्रावधान नहीं होगा।
7. सड़क की अलायनमेंट लोक निर्माण विभाग से अनुमोदित होनी चाहिए ताकि जीप योग्य सड़क को बाद में अपग्रेड करके बस योग्य सड़क लोक निर्माण विभाग के मानदंडों के अनुसार बनाया जा सकें।

#### **5. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना:**

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993-94 से संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को आरम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत माननीय संसद सदस्यों द्वारा अपने - अपने निर्वाचन क्षेत्रों के पूंजीगत छोटे-छोटे कार्यों कमशः पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, जनस्वास्थ्य और सड़कों इत्यादि को करने की अनुशंसा की जाती है। कार्यों की स्वीकृतियां उपायुक्तों द्वारा प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा



प्रत्येक संसद सदस्य को प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए उनकी अनुशंसा पर विभिन्न कार्यों के लिए जारी की जाती है।

**संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निम्न सेक्टर की स्कीमों को किया जा सकता है:-**

1. पेयजल सुविधा।
2. शिक्षा।
3. विद्युत सुविधा।
4. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
5. सिंचाई सुविधाएं।
6. गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत।
7. अन्य लोक सुविधाएं।
8. रेलवे, सड़कें, पगडंडी और पुल।
9. सफाई और जन स्वास्थ्य।
10. खेलकूद।
11. पशु देखभाल, डेयरी तथा मत्स्य पालन संबंधी कार्य।
12. कृषि से संबंधित कार्य।
13. हथकरघा बुनकरों के लिए क्लस्टर विकास से संबंधित कार्य।
14. शहरी विकास से संबंधित कार्य।

## **VI. जनशक्ति एवं रोजगार प्रभाग :**

जनशक्ति एवं रोजगार प्रभाग को निम्न प्रमुख कार्य सौंपे गये हैं :-

### **(i) जनशक्ति की तथ्य पुस्तिका तैयार करना:**

जनशक्ति एवं रोजगार विकासात्मक योजना का अभिन्न अंग है। यह जरूरी हो गया है कि राज्य स्तर पर तकनीकी और जनशक्ति के विभिन्न पहलुओं को कवर करने के लिए जनशक्ति सूचना जानकारी प्रणाली विकसित की जाए। इस प्रणाली की महत्वता को ध्यान में रखते हुए योजना विभाग में गठित जनशक्ति एवं रोजगार प्रभाग जनशक्ति जानकारी से सम्बन्धित सूचना का संग्रहण, संकलन और सारणीयन कर इसका सारांश एक पुस्तिका “Fact Book of Manpower” के रूप में प्रकाशित करता है।

इस पुस्तिका प्रकाशन का कार्य एक नियमित प्रकृति का है क्योंकि समय समय पर इस कार्य को करने हेतु अनुवर्ती और संशोधन की आवश्यकता होती है तथा सांख्यिकीय डाटा तालिकाओं सहित जनसंख्या, जनशक्ति, रोजगार, बेरोजगारी, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य संस्थानों के बारे में सीधे प्रशिक्षण और रोजगार से संबंधित संकलित किया जाता है।

### **(ii) ई.एम.आई. कार्यक्रम तथा उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट:**

रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के तहत जनशक्ति एवं रोजगार प्रभाग द्वारा जिलों/क्षेत्रीय रोजगार कार्यालयों से डाटा का संग्रहण किया जाता है तथा ‘संगठित क्षेत्र में रोजगार के त्वरित आकलन’ रिपोर्ट को हर वर्ष संकलित किया जाता है। इस रिपोर्ट में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के प्रत्येक तिमाही के अंत के आंकड़ों की स्थिति को शामिल किया जाता है।

## VII. बाह्य-सहायता परियोजना प्रभाग:

योजना विभाग के बाह्य सहायता परियोजना प्रभाग को विभिन्न विभागों के परियोजना प्रस्तावों को बाह्य वित्त सहायता प्राप्त करने हेतु परियोजनाओं के विश्लेषण का कार्य दिया गया है। योजना विभाग के इस कक्ष का मुख्य कार्य राज्य के परियोजना प्रस्तावों को बाह्य सहायतार्थ प्राधिकरणों, निजी निवेशकर्ताओं व केन्द्रीय सरकार को वित्तीय प्रबन्धन के लिए प्रेषित किये जाने से पूर्व उनका तकनीकी, प्रशासकीय एवं वित्तीय पहलुओं के दृष्टिगत राज्य के आर्थिक संसाधनों को देखते हुए विस्तृत विश्लेषण करना है। उपरोक्त के अतिरिक्त यह प्रभाग सभी बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की समीक्षा एवं अनुश्रवण करता है। यह प्रभाग सहायता प्रदान करने वाली विभिन्न एजेंसियों के साथ परियोजनाओं के चिन्हांकन तथा समीक्षा हेतु पत्राचार करता है। प्रशासनिक सचिव, योजना, हि०प्र० सरकार को प्रदेश की सभी बाह्य-सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

इन परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यन्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कार्यन्वयन एजेंसियों से वित्तीय व भौतिक उपलब्धियों की रिपोर्ट त्रैमासिक आधार पर प्राप्त की जाती है। इस प्रभाग द्वारा बाह्य सहायता प्राप्त करने हेतु विभिन्न विभागों के परियोजना प्रस्तावों को भारत सरकार को प्रेषित करने के संदर्भ में परामर्श प्रदान किए जाते हैं।

विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.), जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण (JICA), जी. आई. जैड., ए.एफ.डी. (फ्रांसीसी सरकार की एजेंसी) तथा के.एफ.डब्ल्यू. (जर्मन एजेंसी), न्यू डवेलपमेंट बैंक आदि अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों तथा भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिकाओं को, परियोजना प्रस्ताव आमन्त्रित करने के लिए, सम्बन्धित विभागों को प्रेषित किया जाता है तथा उनसे यह आग्रह किया जाता है कि वे राज्य की प्राथमिकताओं को देखते हुये परियोजना प्रस्ताव तैयार करें। योजना विभाग में विभिन्न विभागों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को तकनीकी, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, वित्तीय मापदण्डों के दृष्टिगत विश्लेषण करके अनुमोदित किया जाता है।

### हिमाचल प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं:

क्र० सं०	परियोजना का नाम	डोनर एजेंसी	नोडल विभाग	कुल लागत	रुपये करोड़ों में	
					परियोजना प्रारम्भ की तारीख	अवधि समाप्ति की तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.	हि०प्र० राज्य सड़क परियोजना	विश्व बैंक	लोक निर्माण विभाग	1802.84	जुलाई.०७	जून.१६
2.	हिमाचल प्रदेश मध्य हिमालयन जलागम विकास परियोजना	विश्व बैंक	वन विभाग	661.44	अक्टूबर-०५	मार्च.१६
3.	स्वां नदी एकीकृत जलागम प्रबन्धन परियोजना	जे० आई० सी० ए०	वन विभाग	227.31	मार्च.०६	मार्च.१६
4.	हिमाचल प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में अधोसंरचना विकास निवेश कार्यक्रम	एशियन डवेलपमेंट बैंक	पर्यटन विभाग	428.22	२०१०	२०२०
5.	हि०प्र० फसल विविधीकरण उन्नत परियोजना	जे० आई० सी० ए०	कृषि विभाग	321.00	जुलाई.११	मार्च.१८

1	2	3	4	5	6	7
6.	क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन निवेश कार्यक्रम	एशियन डवैलपमेंट बैंक	विद्युत विभाग	1927.00	जनवरी.12	दिसम्बर.18
7.	विद्युत परियोजनाएं	एशियन डवैलपमेंट बैंक	विद्युत विभाग	6673.87	नवम्बर.08	जून.16
8	हि0 प्र0 फॉरेस्ट ईको सिस्टम जलवायु प्रूफिंग परियोजना	के.एफ.डब्ल्यू	वन विभाग	308.45	अप्रैल.15	मार्च.22
9	हि0 प्र0 उद्यान विकास परियोजना	विश्व बैंक	उद्यान विभाग	1134.00	अगस्त.16	जुलाई.23
कुल योग				13484.13		

### **नई बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति :**

उपरोक्त चालु परियोजनाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित नई परियोजनाएं या तो आरम्भ की जा चुकी है अथवा निकट भविष्य में चालु होने वाली है:

- राष्ट्रीय हाईड्रोलॉजी परियोजना:** 70 करोड़ रुपये की इस परियोजना को 4 मर्दों के अन्तर्गत 8 वर्षों के लिए मंजूर की गई है जिसका आरम्भिक चरण 2015-16 से 2019-20 तक है। इस परियोजना के अन्तर्गत पूरे राज्य में नए स्टेशनों की स्थापना व मौजूदा स्टेशनों के automation द्वारा राज्य के हाईड्रोमीटेरोलॉजिकल नेटवर्क को मजबूत करने का प्रस्ताव है तथा वर्ष 2017-18 के लिए इस परियोजना के अन्तर्गत 3.00 करोड़ रुपये परिव्यय प्रस्तावित है।
- हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना :** 640 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना ADB से वित्त पोषित करने हेतु स्वीकृत कर ली गई है । इस परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा कौशल तथा आजीविका प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समन्वित करने के लिए निजी उद्योगों के सक्रिय सहयोग से प्रदेश के युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में रोजगार व स्वरोजगार के प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे । यह परियोजना वर्ष की अवधि में कार्यान्वित की जाएगी। इस परियोजना के अन्तर्गत सभी गतिविधियों को योजना विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत स्थापित हि0 प्र0 कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। वित्तिय वर्ष 2017-18 के लिए इस परियोजना के अन्तर्गत 1.40 करोड़ रु0 का परिव्यय प्रस्तावित है।
- एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली परियोजना:** वित्तीय प्रबन्धन की यह परियोजना राज्य स्तर पर ट्रेजरी, लेखा, व लॉटरी विभाग द्वारा निष्पादित की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए इस परियोजना के लिए 10.00 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित है।

इन परियोजनाओं के अतिरिक्त शहरी क्षेत्र की सीवरेज सिस्टम व ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों के विकास से सम्बन्धित परियोजनाएं तथा ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र से सम्बन्धित कुछ अन्य परियोजनाएं भारत सरकार व डोनर एजेंसियों के साथ वार्ता के विभिन्न चरणों में पाईपलाईन में है तथा जिसके निकट भविष्य में आरम्भ होने की सम्भावना है।

### **राज्य स्तर पर नवाचार :**

हिमाचल प्रदेश को एक इनोवेटिव राज्य के रूप में परिवर्तित करने के लिए विभिन्न विभागों को नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करने व इन क्षेत्रों के अनुभवों के आदान-प्रदान द्वारा राज्य स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्न कदम उठाए गये हैं।

#### **I. राज्य नवाचार परिषद का गठन:-**

राज्य नवाचार परिषद का गठन हिमाचल सरकार द्वारा 7 जनवरी, 2011 को मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में हुआ था जिसमें राज्य के सम्बन्धित

विभागों के प्रशासनिक सचिवों व विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस परिषद की परिधि के अन्तर्गत कुछ और संस्थानों जैसे एनआईटी, हमीरपुर, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आईआईटी मण्डी, हिमाचल प्रदेश राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी व पर्यावरण परिषद् तथा उद्योग विभाग को लाने के लिए 4 अगस्त, 2014 व 31 दिसंबर, 2015 को इस परिषद का विस्तार किया गया।

**II. राज्य नवाचार फण्ड :** राज्य में विभिन्न विभागों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने तथा इस क्षेत्र में नई पहल आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य नवाचार फण्ड का गठन किया गया है। इस फण्ड के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए दिशा-निर्देशों को राज्य नवाचार परिषद की स्वीकृति के पश्चात अधिसूचित कर दिया गया है।

### **राज्य इनोवेशन फंड के अन्तर्गत कार्यान्वित स्कीमें/परियोजनाएं**

गत वर्षों में विभिन्न विभागों की 2.24 करोड़ रुपये से अधिक की नौ स्कीमें/परियोजनाएं इस फंड के अन्तर्गत कार्यान्वयन हेतु स्वीकार की गई हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान इस फंड के अन्तर्गत 1.10 करोड़ रुपये का प्रवाधान किया गया था तथा विभिन्न विभागों की निम्न 5 स्कीमें/परियोजनाएं कार्यान्वयन हेतु स्वीकार की गई हैं:

**1. हिमुडा के आवंटन व प्रशासनिक शाखा के ऑटोमेशन के प्रथम चरण का कार्यान्वयन :** इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य हिमुडा की विभिन्न गतिविधियों को एकीकृत कर केन्द्रित करना, फील्ड ऑफिस व हैड ऑफिस के बीच सूचना के कुशल विनिमय को सक्षम करना तथा अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं को automate करने के लिए परिष्कृत प्रबन्धन सूचना प्रणाली (MIS) को विकसित करना है। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य अभिनव निधि से 25.00 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।

**2. कचरा एकत्रित करने के लिए निरंतर कचरा एकत्रित करने की प्रणाली का प्रोटोटाइप विकसित करना:** NIT हमीरपुर के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग विभाग की यह परियोजना समय की बर्बादी के बिना निरंतर कचरा इकट्ठा करने की प्रणाली का एक प्रोटोटाइप विकसित करने से सम्बन्धित है। इस प्रणाली में कचरे के आसान निपटान के लिए पॉलिबैग के साथ एक इनबिल्ट कूड़ेदान का प्रावधान है जिसके कारण बाहरी सहायता के बगैर व बिना समय बर्बाद किए आसानी से कचरे का निपटान संभव है। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 1,08,000 रुपये राज्य इनोवेशन फंड से मंजूर किए गए हैं।

**3. RFSL मंडी में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में अत्याधुनिक डिजिटल फॉरेंसिक सुविधाओं के विकास से सम्बन्धित परियोजना:**

इस परियोजना में image व video enhancement के लिए intensity range enhancement व denoising विधियों का विकास, single view metrology द्वारा geometric scene विश्लेषण, speaker identification व speech enhancement आदि सुविधाओं से सुसज्जित उपकरणों के लिए प्रोटोटाइप विकसित करना प्रस्तावित है। ये उपकरण डिजिटल फॉरेंसिक फील्ड से सम्बन्धित समस्याओं को वास्तविक रूप से हल करने में सहायक सिद्ध होंगे तथा इसे कार्यान्वित करने के लिए 16,80,000 रु० की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

**4. RFSL- NR धर्मशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं को स्थापित करने के लिए परियोजना:**

क्षेत्रीय फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी धर्मशाला को VC सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए बुनियादी इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए SInF से 7.00 लाख रुपये की यह परियोजना वित्त पोषण हेतु स्वीकृत की गई है। इस सुविधा की स्थापना से हि०प्र० के विभिन्न अदालतों के साथ कनेक्टिविटी हो जाने से इस विभाग की सर्विस डिलीवरी सिस्टम में सुधार होगा तथा साथ ही विशेषज्ञों द्वारा राज्य की विभिन्न अदालतों में साक्ष्यों को अधिप्रमाणित करने के लिए की जाने वाली यात्रा में लगने वाले बहुमूल्य समय की भी बचत होगी।

**5. आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र चियोग में मिनी हर्बल गार्डन व एक्युप्रेसर ट्रेक की स्थापना:** इस स्वास्थ्य केन्द्र में मिनी हर्बल गार्डन व एक्युप्रेसर ट्रेक को स्थापित करने की 1.49 लाख की यह परियोजना SPF से वित्त पोषण हेतु स्वीकृत की गई है। इस

परियोजना का मुख्य उद्देश्य संस्थान के परिसर में औषधीय पौधों को बढ़ाने/उगाने व संरक्षित करने के उद्देश्य से एक हरे व पर्यावरण के अनुकूल परिसर की स्थापना करने के साथ-2 रोगियों को तनाव मुक्त रखने, रक्त परिसंचरण में वृद्धि करने, दर्द को कम करने व आध्यात्मिक कला व जीवंत स्वास्थ्य को विकसित करने में सहायक एक्यूप्रेशर ट्रेक को स्थापित करना है।

### III. नवाचार अवार्ड योजना:

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में शुरू किए गए State Innovation Award के अन्तर्गत प्रदेश में कृषि व बागवानी, शिक्षा, फूड प्रोसैसिंग व मैनुफैक्चरिंग, सामाजिक विकास, पर्यटन विकास तथा सरकारी क्षेत्र में की गयी विशेष इनोवेशन्स को प्रोत्साहित करने हेतु सम्मान स्वरूप वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

#### हि0 प्र0 राज्य ईनोवेशन अवार्ड स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 के लिए चयनित नवाचार (Innovations)

वर्ष 2015-16 के लिए राज्य स्तरीय Innovation Award के लिए चयनित विभिन्न क्षेत्रों की निम्न 5 इनोवेशन्स को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 15 अप्रैल, 2017 को चम्बा जिला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में पुरस्कृत किया गया किया गया है।

##### 1. कृषि व बागवानी क्षेत्र में चयनित ईनोवेशन/विजेता :-

कृषि व बागवानी क्षेत्र में डॉ0 वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन के वैज्ञानिकों डॉ0 कमल शर्मा व डॉ0 संजीव ठाकुर द्वारा बंदरों व आवारा पशुओं से प्रभावित क्षेत्रों में हरड़ (Harar) की उच्च पैदावार व early bearing प्रजाति को विकसित करने के लिए Innovation Award से सम्मानित किया गया है। हरड़ की यह प्रजाति केवल तीन वर्ष में फल देना शुरू कर देती है जबकि परम्परागत विधि से तैयार पौधों में फसल 10-12 वर्ष पश्चात् तैयार होती है।

##### 2. सामाजिक विकास क्षेत्र में चयनित ईनोवेशन/विजेता :- डॉ0 सुधीर शर्मा, एसोसिएट प्रोफ़ेसर, न्यूरोलॉजी विभाग, IGMCI शिमला ने अपने Tele-Stroke project के माध्यम से ischemic Stroke के दौरान दूर दराज के क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए Social Networking विधियों जैसे Whatsap आदि का उपयोग करने का एक सरल व innovative तरीका अपनाया है। जिसके द्वारा दूर दराज के किसी भी स्वास्थ्य संस्थान में प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस stroke के दौरान विशेषज्ञ की अनुपस्थिति में भी प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की जा सकती है। सामाजिक विकास के क्षेत्र में दिये गए इस योगदान के लिए इस ईनोवेशन को स्टेट ईनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

##### 3. फूड प्रोसैसिंग व मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र में चयनित ईनोवेशन/विजेता :- M/s R.R. Enterprises के Ready to Mix Spices उत्पादों को फूड प्रोसैसिंग व मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र में इस Award से सम्मानित किया गया है। ये उत्पाद समाज के विभिन्न वर्गों जैसे छात्रों, श्रमिकों, व आम लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हुए हैं क्योंकि भोजन की गुणवत्ता व पौष्टिकता बनाए रखने के साथ-2 ये उत्पाद समय व धन की बचत भी करते हैं। जिसके कारण बचे हुए समय का सदुपयोग उत्पादकता वाले कार्यों में किया जा सकता है। पकाने की विधि सरल होने के कारण लोगों को

अनावश्यक जंक फूड व Packed भोजन खाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता।

4. **शैक्षणिक क्षेत्र में चयनित इनोवेशन/विजेता :-** 3-5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में Basic साक्षरता व संख्यात्मक ज्ञान को समझने व पाए गए Learning gaps में अप्रत्याशित सुधार लाने हेतु DIET मंडी तथा जिला प्रशासन मंडी के सहयोग से उड़ान (UDAAN) कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए DIET मंडी को शैक्षणिक क्षेत्र में इस योगदान के लिए Innovation Award से सम्मानित किया गया है।
5. **सरकारी क्षेत्र में चयनित इनोवेशन/विजेता :-** Town & Country Planning विभाग, हिमाचल प्रदेश में भवन निर्माण की अनुमति से सम्बन्धित सभी सुविधाओं को ऑनलाइन web interface के माध्यम से आम नागरिकों को प्रदान कर रहा है। आम जनता को दी जा रही इन सेवाओं तथा विभागीय कार्य प्रणाली को पारदर्शी, पेपरलेस व आसान बनाने के लिए e-services प्रोजेक्ट को कुशलतापूर्वक कार्यान्वित करने हेतु इस विभाग को सरकारी क्षेत्र में State Innovation Award से सम्मानित किया गया है।

## VIII. कौशल विकास प्रभाग

राज्य में कौशल विकास से सम्बन्धित कार्य योजना विभाग द्वारा समन्वित किया जा रहा है। वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य में कौशल विकास से सम्बन्धित गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए निम्न कार्य किए हैं:-

1. कौशल विकास वार्षिक योजना 2016-17 सभी सम्बन्धित विभागों से प्राप्त प्रस्तावों को शामिल कर तैयार की गई है।
2. कौशल विकास योजना नीति दस्तावेज तैयार करके सभी सचिवों व विभागाध्यक्षों को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध करवाया गया।
3. मु0 640 करोड़ रुपये की हिमाचल प्रदेश कौशल विकास योजना को स्वीकृति के पश्चात भारत सरकार से बजट हेतु परियोजना तत्परता दस्तावेज तैयार किए गए तथा उन्हें ए.डी.बी. व भारत सरकार को भेजा गया।
4. कौशल विकास निगम को सुचारु रूप से चलाने के लिए जरूरत आधारित स्टाफ re-employment व secondment आधार पर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई। इसके लिए सचिव, कार्मिक विभाग की अध्यक्षता में सर्विस कमेटी (Service Committee) का गठन किया गया तथा विषय आधारित ज्ञापन तैयार कर हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम हेतु जरूरी स्टाफ की स्वीकृति ली गई।
5. राज्य के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए छः जिलों में 1000 प्रशिक्षुओं हेतु कौशल विकास निगम के माध्यम से प्रयोगिक परियोजना शुरू की गई है।

- 6- वर्ष 2017-18 में 14000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण हेतु एक परियोजना को तैयार कर भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को स्वीकृति हेतु भेजा गया तथा परिणामस्वरूप भारत सरकार से प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के तहत मु0 21,55,60,800 रुपये की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई।

## **IX. नाबार्ड-ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि (आर.आई.डी.एफ.) प्रभाग:**

वर्ष 1995-96 का वार्षिक बजट प्रस्तुत करते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री ने ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि की घोषणा करते हुए कहा था कि नाबार्ड राज्य सरकारों के आधारभूत संरचना जुटाने के लिए विभिन्न मदों जैसे मध्यम तथा लघु सिंचाई, भू-संरक्षण तथा अन्य ग्रामीण मूलभूत परियोजनाओं जिसमें ग्रामीण सड़कें, मार्केट यार्ड इत्यादि के लिए ऋण उपलब्ध करवाएगा। आरम्भ में यह योजना आर.आई.डी.एफ.-1 के अन्तर्गत चालू स्कीमों को पूर्ण करने के लिए थी जिसमें नाबार्ड से 50 प्रतिशत ऋण सहायता उपलब्ध किए जाने का प्रावधान था। इसके सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के फलस्वरूप इस योजना को आर.आई.डी.एफ. II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI तथा XXII के अन्तर्गत भी जारी रखा गया है तथा इसकी ऋण सहायता राशि को भी 90/95 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया।

2. राज्य सरकार नाबार्ड से आर0 आई0 डी0 एफ0 के अन्तर्गत अनेक प्रकार के विकासात्मक गतिविधियों के लिए ऋण प्राप्त कर रही है। मुख्य विकासात्मक गतिविधियां जिन के लिए राज्य सरकार ने नाबार्ड से परियोजनाएँ अनुमोदित करवाई हैं या ऋण सहायता के लिए भेजी हैं, का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :

1. सड़कों एवं पुलों का निर्माण।
2. सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण।
3. बाढ़ नियन्त्रण कार्यों का निर्माण।
4. पेयजल परियोजनाओं का निर्माण।
5. प्राथमिक पाठशालाओं के भवन का निर्माण “सरस्वती बाल विद्या संकल्प परियोजना”।
6. नागरिक सूचना केन्द्रों की स्थापना।
7. ई-अभिशासन (E-Governance)।
8. वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण।
9. जल प्रवाह विकास योजना।
10. पशु स्वास्थ्य के लिए अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण।
11. Precision Farming पद्धति अपनाकर नकदी फसलों का उत्पादन परियोजना (पोलीहाऊस एवं लघु सिंचाई)।
12. लघु सिंचाई एवं सम्बन्धित संरचना द्वारा कृषि का विविधीकरण परियोजना।
13. वातानुकूलित भण्डारण निर्माण।

3. नाबार्ड द्वारा दिनांक 31-03-2017 तक प्रदेश सरकार को 6343 करोड़ रु0 की राशि विभिन्न परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता के रूप में स्वीकृत की जा चुकी है जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

( करोड़ रु0 में)

द्विच संख्या	कार्यक्रम की अवधि	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	नाबार्ड ऋण सहायता	राज्य अंशदान	कुल स्वीकृत राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
आर.आई.डी.एफ -I	1995-96 से 1997-98	77	14.23	4.90	19.13
आर.आई.डी.एफ -II	1996-97 से 1998-99	66	52.96	6.32	59.28
आर.आई.डी.एफ -III	1997-98 से 1999-2000	28	51.12	5.12	56.24
आर.आई.डी.एफ -IV	1998-99 से 2000-01	66	87.81	3.48	91.29
आर.आई.डी.एफ -V	1999-2000 से 2001-02	680	110.36	6.80	117.16
आर.आई.डी.एफ -VI	2000-01 से 2002-03	1053	127.20	10.15	137.35
आर.आई.डी.एफ-VII	2001-02 से 2003-04	325	168.24	8.90	177.14
आर.आई.डी.एफ-VIII	2002-03 से 2004-05	237	169.29	13.80	183.09
आर.आई.डी.एफ -IX	2003-04 से 2005-06	182	141.70	19.35	161.05
आर.आई.डी.एफ -X	2004-05 से 2006-07	146	91.64	9.96	101.60
आर.आई.डी.एफ -XI	2005-06 से 2007-08	266	224.67	29.73	254.40
आर.आई.डी.एफ-XII	2006-07 से 2008-09	379	272.30	36.17	308.47
आर.आई.डी.एफ-XIII	2007-08 से 2010-11	359	308.06	32.55	340.61
आर.आई.डी.एफ-XIV	2008-09 से 2011-12	136	424.82	28.13	452.95
आर.आई.डी.एफ-XV	2009-10 से 2012-13	223	454.13	36.98	491.11
आर.आई.डी.एफ-XVI	2010-11 से 2013-14	186	394.53	37.16	431.69
आर.आई.डी.एफ-XVII	2011-12 से 2014-15	225	423.69	41.81	465.50
आर.आई.डी.एफ-XVIII	2012-13 से 2015-16	164	432.16	44.32	476.48
आर.आई.डी.एफ-XIX	2013-14 से 2016-17	142	496.09	65.18	561.27
आर.आई.डी.एफ-XX	2014-15 से 2017-18	161	707.61	58.89	766.50
आर.आई.डी.एफ-XXI	2015-16 से 2018-19	170	644.94	60.75	705.69
आर.आई.डी.एफ-XXII	2016-17 से 2019-2020	125	545.54	60.20	605.74
कुल योग: ( I से XXII)		5396	6343.09	620.65	6963.74



4. दिनांक 31-03-2017 तक उपरोक्त स्वीकृत नाबार्ड ऋण सहायता राशि 6343 करोड़ रु0 में से प्रदेश सरकार ने 4465 करोड़ रु0 की ऋण राशि नाबार्ड से प्राप्त कर ली है। नाबार्ड से प्राप्त आर0आई0डी0एफ0 कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति प्राप्तियों का वर्ष 1995-96 से 2016-17 तक विवरण निम्न तालिका में है :-

वर्ष	प्रतिपूर्ति प्राप्तियाँ (करोड़ रु0 में)
1.	2.
1995-96	1.60
1996-97	5.31
1997-98	35.44
1998-99	40.65
1999-00	56.01
2000-01	106.92
2001-02	116.44
2002-03	141.58
2003-04	142.35
2004-05	83.17
2005-06	125.09
2006-07	140.38
2007-08	200.00
2008-09	220.00
2009-10	300.00
2010-11	294.49
2011-12	305.51
2012-13	400.00
2013-14	350.00
2014-15	400.00
2015-16	500.00
2016-17	500.00
<b>Total</b>	<b>4464.94</b>

5. नाबार्ड ऋण के अन्तर्गत लक्ष्य एवं प्राप्तियाँ ( 2006-07 से 2016-17) :

( करोड़ रु0 में)

क्रम संख्या	वर्ष / ट्रांच	ऋण स्वीकृत लक्ष्य	उपलब्धियाँ	प्रतिशतता
1.	2006-07 (XII)	277.00	273.48	98.73
2.	2007-08 (XIII)	298.00	299.26	100.42
3.	2008-09 (XIV)	406.00	425.12	104.71
4.	2009-10 (XV)	398.00	454.50	114.20
5.	2010-11 (XVI)	400.00 (एचपीसी द्वारा अनुमोदित) (560.00-नाबार्ड)	412.90	103.22
6.	2011-12 (XVII)	400.00 (एचपीसी द्वारा अनुमोदित) (540.00-नाबार्ड)	423.69	105.93
7.	2012-13 (XVIII)	400.00 (एचपीसी द्वारा अनुमोदित) (500.00-नाबार्ड)	432.16	108.04
8.	2013-14 (XIX)	475.00 (एचपीसी द्वारा अनुमोदित)	496.09	104.44
9.	2014-15 (XX)	765.00	707.61	92.50
10.	2015-16 (XXI)	514.00	644.94	125.47
11.	2016-17 (XXII)	620.00 (एचपीसी द्वारा अनुमोदित) (545.00-नाबार्ड)	545.54	87.99

6. प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजना / स्कीमों को नाबार्ड को स्वीकृति के लिए प्रेषित करना तथा योजनाओं की समीक्षा, इत्यादि के सम्बन्ध में योजना विभाग को नोडल विभाग घोषित किया है ।

7. वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आर0आई0डी0एफ0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाओं की समीक्षा हेतु आयोजित बैठकों का ब्यौरा :-

क्रम संख्या	बैठक का नाम	बैठक की तिथि एवं स्थान	बैठक की अध्यक्षता
1.	2.	3.	4.
1.	आर0आई0डी0एफ0 की 45वीं उच्च स्तरीय समिति (HPC)की बैठक	23-04-2016 शिमला	मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
2.	आर0आई0डी0एफ0 की 46वीं उच्च स्तरीय समिति (HPC)की बैठक	29-11-2016 शिमला	मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
3.	विधायकों के साथ बैठके	30 व 31 जनवरी, 2017 शिमला	माननीय मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त वर्णित बैठकों के अतिरिक्त, क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड शिमला में सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ द्विमासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं । इन बैठकों में कार्यकारी विभागों के अधिकारियों के अतिरिक्त नाबार्ड एवं योजना विभाग के अधिकारी भी भाग लेते हैं । मासिक समीक्षा बैठकों में नाबार्ड ऋण पोषित योजनाओं की विस्तृत भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा की जाती है तथा सम्बन्धित विभागों को योजनाओं के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं । इन बैठकों से योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन में काफी सहायता मिलती है। उपरोक्त समीक्षा बैठकों के अतिरिक्त सम्बन्धित प्रशासनिक सचिवों एवं विभागाध्यक्षों के स्तर पर भी समीक्षा बैठकें की जाती हैं। जिला स्तर पर सम्बन्धित उपायुक्तों की अध्यक्षता में भी आयोजित समीक्षा बैठकों में नाबार्ड ऋण पोषित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाती है।

## X. 20-सूत्रीय कार्यक्रम प्रभाग:

### बीस सूत्रीय कार्यक्रम-2016-17

बीस सूत्रीय कार्यक्रम-2006 (बीसूका-2006) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के निर्धन व्यक्तियों की निर्धनता दूर करने एवं उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है । बीस सूत्रीय कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पहलुओं जैसे कि गरीबी उन्मूलन, रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, कृषि, भू-सुधार, सिंचाई, पेयजल, समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण एवं सशक्तिकरण, उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण, ई-गवर्नेंस, इत्यादि कार्यक्रमों को शामिल किया गया है ।

राष्ट्रीय स्तर पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा बीस सूत्रीय कार्यक्रम-2006 में शामिल कार्यक्रमों/योजनाओं को राज्य सरकार एवं सम्बन्धित केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों से प्राप्त प्रगति प्रतिवेदनों के आधार पर अनुश्रवण किया जाता है।

पुनःसंरचित बीस सूत्रीय कार्यक्रम-2006 में मूल रूप में 20 सूत्र और 65 अनुश्रवण योग्य मदें हैं जो कि प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक वर्ष के लिए अलग-अलग होती हैं । 2009-10 तक बीस सूत्रीय कार्यक्रम-2006 के कार्यान्वयन का आकलन भारत सरकार द्वारा राज्यों की रैंकिंग के आधार पर होता था परन्तु उसके उपरान्त [रैंकिंग](#) को समाप्त कर दिया गया है ।

प्रत्येक अनुश्रवण/निगरानी वाली मद का त्रैमासिक/वार्षिक उपलब्धि के आधार पर “बहुत अच्छा”, “अच्छा” और “खराब/चिन्ताजनक” श्रेणी में वर्गीकरण निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	प्रतिशतता उपलब्धि	श्रेणी
1.	2.	3.
1.	90 प्रतिशत एवं उससे अधिक	बहुत अच्छा
2.	80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत	अच्छा
3.	80 प्रतिशत से नीचे	खराब/चिन्ताजनक

2007 से बीस सूत्रीय कार्यक्रम-2006 के समन्वय, समीक्षा, अनुश्रवण तथा त्रैमासिक / वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनों हेतु योजना विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है ।

हिमाचल प्रदेश का बीस सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन में गत वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है । राष्ट्रीय स्तर पर बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन में राज्य का वर्षवार विवरण निम्न है:-

क्रम संख्या	वर्ष	राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश की <a href="#">उपलब्धि/स्थान</a>
1.	2.	3.
1.	2012-13	“ <b>Very Good</b> ” in all items except Road Construction (PMGSY) which was ranked “Good” (80% to 90%).
2.	2013-14	Placed in the “ <b>Very Good</b> ” Category
3.	2014-15	“ <b>Very Good</b> ” in all items except Houses Constructed IAY and Houses constructed – EWS/LIG.
4.	2015-16	“ <b>Very Good</b> ” in all items except Area covered under Plantation (Public and Forest lands).

बीस सूत्रीय कार्यक्रम-2006 के प्रभावशाली निष्पादन में विभिन्न जिलों में प्रतिस्पर्धा लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अन्तर जिला श्रेणी/विश्लेषण का कार्य शुरू किया है । इसके अन्तर्गत प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले तीन जिलों को प्रोत्साहन राशि के रूप में

क्रमशः 50 लाख रुपये, 30 लाख रुपये व 20 लाख रुपये प्रदान करने का प्रावधान किया गया है । इस प्रोत्साहन राशि को जिलों की विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है ।

वर्ष 2015-16 में बीस सूत्रीय कार्यक्रम निष्पादन के आधार पर 3 जिलों क्रमशः ऊना ने प्रथम स्थान तथा कांगड़ा एवं सोलन ने संयुक्त रूप से अन्तर जिला विश्लेषण में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।

इन 3 जिलों को एक करोड़ रु0 की ईनाम राशि आवंटित की गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	जिले का नाम	राशि (रु0 लाख में)
1.	2.	3.
1.	ऊना	50.00
2.	कांगड़ा	25.00
3.	सोलन	25.00
योग		100.00

जिला स्तरीय योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समितियाँ सभी जिलों में त्रैमासिक बैठकों में बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करती हैं । इन बैठकों की अध्यक्षता माननीय मुख्य मन्त्री/मन्त्री/विधायक द्वारा की जाती है । इसके अतिरिक्त सभी जिलों में उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी / जिला योजना अधिकारी भी समय-समय पर जिलों में आयोजित की जाने वाली विभिन्न बैठकों में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बीस सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा / अनुश्रवण करते हैं।

राज्य स्तर पर माननीय मुख्य मन्त्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) एवं सलाहकार (योजना), हि0प्र0 की अध्यक्षता में आयोजित विभिन्न बैठकों में भी बीस सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा की जाती है ।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम तथा राज्य, जिला एवं उप मण्डल स्तर की योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समितियों के गठन से सम्बन्धित समस्त /कार्य/पत्राचार, वर्ष 2016-17 के दौरान बीस सूत्रीय कार्यक्रम प्रभाग द्वारा निष्पादित किये गये हैं।

वर्ष 2016-17 के लिए, 31 दिसम्बर, 2016 तक मदवार लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का विवरण निम्न प्रकार से है :-

**Twenty Point Programme 2016-17**  
**Achievements under TPP for the year 2016-17**  
**upto the 3<sup>rd</sup> quarter ending 31 December, 2016**

Item Code	Item Name/Sub Item Name	Unit	Annual Targets 2016-17	Cum. ach. upto December, 2016	% age Achievement
1	2	3	4	5	6
<b>01A</b>	<b>Employment generation under the NREG Act</b>				
01A01	No. of job cards issued	No.	NT	1173244	-
01A02	Employment generated	Mandays	NT	15631000	-
01A03	Wages given in cash	Rupees	NT	2407798000	-
<b>01B</b>	<b>National Rural Livelihood Mission (NRLM)</b>				
01B01*	Number of new and revived SHGs brought under NRLM fold during the financial year	No.	1270	856	67.40
01B02	Number of SHGs provided Revolving Fund (RF) during the financial year	No.	640	210	32.81
01E02*	Number of SHGs provided Community Investment Fund (CIF) during the financial year	No.	390	21	5.39
<b>05A</b>	<b>Food Security-Targeted Public Distribution System (TPDS)</b>				
05A02	Food Security: Targeted Public Distribution System (APL+BPL+AAY) (Other than NFSA+NFSA)	Tonnes	NT	383216	-
05B02	Food Security: Below Poverty Line (BPL)	Tonnes	NT	NA	
05D02	Food Security: Antyodaya Anna Yojana (AAY)	Tonnes	NT	NA	-
05E02	Food Grains under NFSA - Normal	Tonnes	NT	147163	
05F02	Food Grains under NFSA – Tide Over	Tonnes	NT	NA	-
	Other than NFSA	Tonnes	NT	235855	-
<b>06A</b>	<b>Rural Housing –PMAY-G</b>				
06A01*	Houses constructed	No.	4874	NA	-
<b>06B</b>	<b>EWS/LIG Houses in Urban Areas</b>				
06B01*	Houses constructed	No.	1312	NA	

Item Code	Item Name/Sub Item Name	Unit	Annual Targets 2016-17	Cum. ach. upto December, 2016 (3 <sup>rd</sup> quarter)	% age Achievement
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
07A03 *	Habitations covered (Partially covered & Slipped back )	No.	1300	722	55.44
07B	Sanitation Programme in Rural Areas				
<b>08E</b>	<b>Institutional Delivery</b>				
08E01	Delivery in institutions	No.	NT	59269	-
<b>10A</b>	<b>SC Families Assisted</b>				
10A02 *	(i)SC Families Assisted under SCA to SCSP and NSFDC	No.	1561	10009	641.19
<b>12A</b>	<b>Universalization of ICDS Scheme</b>				
12A01 *	ICDS Blocks Operational (Cumulative)	No.	78	78	100.00
<b>12B</b>	<b>Functional Anganwadis</b>				
12B01*	Anganwadis Functional (Cumulative)	No.	18925	18925	100.00
<b>14A</b>	<b>No. of Urban poor families assisted under Seven Point Charter.</b>				
14A01 *	Poor Families Assisted	No.		NR	-
<b>15A</b>	<b>Afforestation ( Public and Forest Lands)</b>				
15A01*	Area Covered under Plantation	Hectares	20728	7969	38.45
15A02 *	Seedlings planted	In No.	13473000	7936488	58.90
<b>17A</b>	<b>Rural Roads –PMGSY</b>				
17A01 *	Length of Road Constructed	Kilometer	500	588	117.6
<b>18B</b>	<b>Deendayal Upadhayaya Gram Jyoti Yojana (DDUGJY)</b>				
18B01*	Villages electrified	No.	34	4	11.77
<b>18D</b>	<b>Energising pump sets</b>				
18D01*	Pumps sets energized	No.	1138	1513	132.95
<b>18E02</b>	<b>Supply of Electricity</b>				
18C02	Electricity supplied	Million units	NT	6756	-

## XI. रेलवे प्रभाग :

राज्य में रेल सम्बन्धित कार्यों के लिए योजना विभाग प्रशासनिक विभाग है। रेलवे प्रभाग द्वारा रेलवे से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों जैसे भू-अधिग्रहण, समन्वय, अनुश्रवण व समीक्षा, इत्यादि का कार्य किया जाता है। वर्ष 2016-17 के दौरान उत्तर रेलवे के अधिकारियों, RVNL, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न सम्बन्धित विभागों के साथ समीक्षा व समन्वय बैठकों का आयोजन किया गया। प्रदेश में मुख्य रूप से निम्न तीन रेल लाईनों का भू अर्जन / निर्माण कार्य किया जा रहा है।

**1. भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी- ब्रॉडगेज रेल लाईन (63.1 कि०मी०):** भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी नई रेल लाईन का निर्माण कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) द्वारा किया जा रहा है। CCEA के निर्णय के अनुरूप, 25 प्रतिशत लागत राज्य सरकार (70 करोड़ रु० से अधिक की समस्त भू अधिग्रहण लागत प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जायेगी), 25 प्रतिशत रेलवे मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा व 50 प्रतिशत वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इस रेल लाईन की संशोधित लागत रु० 1046 करोड़ से बढ़कर रु० 2967 करोड़ हो गई है। रेल लाईन के लिए हिमाचल प्रदेश में पड़ने वाली भूमि की अधिग्रहण प्रक्रिया SDM-cum-LAO (Rail) Bilaspur द्वारा भू-मालिकों से बातचीत के माध्यम से आरम्भ की जा चुकी है। इस रेल लाईन के निर्माण की समीक्षा PRAGATI के माध्यम से प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा समय-2 पर की जाती है। वर्ष 2009-10 में रु० 10 करोड़ तथा 2016-17 में इस रेल लाईन के लिये 12 करोड़ रु० दिये गये हैं।

**2. चण्डीगढ़-बददी रेल लाईन (33.23 कि०मी०):** राज्य सरकार ने इस परियोजना लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा वहन करने का निर्णय लिया है। इस रेल लाईन का प्राकलन मु० 1672 करोड़ रु० उत्तर रेलवे मुख्यालय, नई दिल्ली को उत्तर रेलवे चण्डीगढ़ से अनुमोदन हेतु भेजा गया है। इस परियोजना के लिए समय पर भूमि उपलब्ध करवाए जाने के सम्बन्ध में भू-स्वामियों से भूमि खरीद हेतु समझौता प्रक्रिया शुरू की गई है।

**3. नंगल-तलवाड़ा ब्रॉडगेज रेल लाईन (83.74 कि०मी०):** इस रेल लाईन की कुल लम्बाई 83.74 कि०मी० है जिसमें से 62 कि०मी० ट्रैक हिमाचल प्रदेश में आता है। अम्ब-अन्दौरा (44 कि०मी०) रेल लाईन पर यातायात आरम्भ कर दिया गया है। इस परियोजना को पूर्ण करने की लागत लगभग 1200 करोड़ रु० है। अम्ब-अन्दौरा-चिन्तपुरी-दौलतपुर चौक (18 कि०मी०) का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना पूर्ण होने पर जम्मू और कश्मीर के लिए एक अतिरिक्त वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा इस परियोजना को प्राथमिकता दी गई है तथा PRAGATI द्वारा भी इस परियोजना की समीक्षा की जा रही है।

उपरोक्त रेल लाईनों के अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा **(क) पठानकोट-जोगिन्दरनगर नैरोगेज रेल लाईन को ब्रॉडगेज रेल लाईन में परिवर्तित करना तथा इसका विस्तार वाया मण्डी लेह-लद्दाख तक करने तथा (ख) घनौली-बददी-कालाअम्ब-पौंटा साहिब-देहरादून ब्रॉडगेज रेल लाईनों से सम्बन्धित** मामले रेल मन्त्रालय, भारत सरकार, के साथ समय-2 पर उठाए गए हैं।

रेलवे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु राज्य सरकार द्वारा समझौता कमेटियां गठित की गई ताकि राज्य में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं के लिए भू-मालिकों की सहमति से भूमि क्रय की जा सके। सरकार के इस प्रयास से प्रदेश में निर्मित की जाने वाली रेल लाईनों के लिए समय पर भूमि उपलब्ध हो पायेगी। इसके अतिरिक्त भू-अर्जन से सम्बन्धित मुकदमेबाजी भी कम होगी तथा रेल परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध करवाने में होने वाली देरी भी कम होगी जिसके परिणामस्वरूप परियोजना की लागत वृद्धि से बचा जा सकेगा।

## **XII. मूल्यांकन प्रभाग:**

योजना विभाग के मूल्यांकन प्रभाग को विभिन्न महत्वपूर्ण विकासात्मक योजनाओं व परियोजनाओं के मूल्यांकन अध्ययन का कार्य सौंपा गया है। मूल्यांकन का उद्देश्य कार्यान्वयन प्रक्रिया को जांचना है ताकि स्कीमों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आने वाली मुश्किलों व कमियों का पता लग सके और इन तथ्यों पर आधारित कार्यान्वयन प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उपाय/ सुझाव दिए जा सकें। विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों का कार्यान्वयन करने के लिए राज्य स्तर पर तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया गया है।

## **XIII. विधायक प्राथमिकता योजना प्रभाग:**

विधायक प्रभाग द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान निम्न कार्य निष्पादित किए गए:-

- 1 वर्ष 2016-17 के दौरान माननीय मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में सम्पन्न विधायक प्राथमिकताओं की बैठकों की कार्यवाही सभी सम्बन्धित विभागों को अनुवर्ती कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई जिस पर विभागों से अनुवर्ती कार्यवाही प्राप्त होने के पश्चात् संकलित करके सभी माननीय विधायकों को उपलब्ध करवाई गई ।
- 2 वार्षिक बजट 2017-18 के लिए प्राथमिकताओं के निर्धारण हेतु मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में दिनांक 30 एवं 31 जनवरी, 2017 को माननीय विधायकों की बैठकों का आयोजन किया गया ।
- 3 प्रदेश सरकार की अनुमोदित नीति के अनुरूप विधायकों द्वारा तीन विकास शीर्षों सड़क, ग्रामीण पेयजल एवं लघु सिंचाई के अन्तर्गत दो-दो प्राथमिकताओं की योजनाएं नई एवं चालू योजनाओं के अन्तर्गत बजट में शामिल करने के लिए दी जाती हैं । इस प्रकार प्रत्येक विधायक की 6 नई एवं 6 चालू योजनाएं बजट में सम्मिलित की जाती हैं । प्रत्येक विधायक को यह छूट होती है कि वह सभी 6 योजनाएं किसी एक ही विकास शीर्ष अथवा दो विकास शीर्षों या तीनों विकास शीर्षों में प्रस्तावित कर सकते हैं। उपरोक्त के अनुरूप माननीय विधायकों से प्राथमिकताएं प्राप्त होने के उपरान्त



संकलित की गई । संकलित प्राथमिकताओं को “नव व्यय अनुसूची के परिशिष्ट (योजना) माननीय विधायकों द्वारा निर्दिष्ट प्राथमिकताएं वर्ष 2017-18”, के रूप में प्रकाशित किया गया। यह प्रकाशन राज्य के वार्षिक बजट का हिस्सा है ।

4. विधायक प्राथमिकताओं से सम्बन्धित कार्य गतिशील प्रवृत्ति के होने हैं । वर्ष के दौरान विधायकों से योजनाओं में फेरबदल/प्रतिस्थापित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए । इन प्रस्तावों पर सरकार की अनुमोदित नीति के अनुरूप वाँछित कार्यवाही की गई। सम्बन्धित विभागों को विधायकों के प्रस्तावों पर उचित कार्यवाही के निर्देश दिए गए तथा सम्बन्धित विधायकों को भी फेरबदल/प्रतिस्थापित की गई योजनाओं के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से सूचित किया गया ।

#### **XIV. कम्प्यूटर प्रभाग:**

कम्प्यूटरीकरण आवश्यकताओं की विभाग में प्रतिपूर्ति तथा योजना आंकड़ों के एकत्रीकरण एवं सांख्यिकीय आंकड़ों के रख रखाव के लिए कम्प्यूटर प्रभाग की स्थापना की गई है । योजना विभाग द्वारा तैयार किए जाने वाले सभी प्रकाशन रिपोर्टें पहले कम्प्यूटर पर ही तैयार किए जाते हैं तथा उसके उपरान्त मुद्रण करवाया जाता है । यह प्रभाग, विभाग की सॉफ्टवेयर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रभागों के निम्न सॉफ्टवेयर को विकसित करता रहता है :-

1. वार्षिक योजना 2016-17 के लिए जी0एन0 सॉफ्टवेयर का रूपान्तर / सुधार ।
2. आर.आई.डी.एफ. का सॉफ्टवेयर / सुधार ।
3. माननीय विधायकों की प्राथमिकता की स्कीमों के सॉफ्टवेयर का रूपान्तर/सुधार ।
4. स्टेट इनोवेशन कॉउंसिल सॉफ्टवेयर विकसित करना
5. वार्षिक योजना (2016-17) के दस्तावेज का कार्य ।
6. ई-वेतन(हिमकोष) में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन व बकाया वेतन भत्तों व अतिरिक्त मंहगाई भत्तों का कार्य ।
7. माननीय विधायकों की स्कीमों को सॉफ्टवेयर के द्वारा Data Entry.
8. पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के बजट परिलयों का जिलावार एवं एस0ओ0ई0-वार आवंटन ।
9. विभिन्न कार्याक्रमों/स्कीमों की मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट्स ।

10. विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों की आयकर विवरणिकाओं को तैयार करने में सहायता के लिए सॉफ्टवेयर का रूपान्तर/सुधार ।
11. माननीय विधायकों के साथ योजना के सूत्रीकरण से सम्बन्धित बैठकों में लिए गए निर्णयों की अनुवर्ती कार्यवाही का कम्प्यूटरीकरण करने तथा वर्ष 2015-16 के लिए माननीय विधायकों द्वारा प्रेषित की गई प्राथमिकता वाली स्कीमों का बजट दस्तावेज तैयार करने में सहायता ।
12. Fact Book on Manpower तथा Quick Estimates 2015-16 के दस्तावेजों को तैयार करने में सहायता ।
13. विभाग की विभिन्न बैठकों के लिए Power Point Presentation.
14. 20-सूत्रीय कार्यक्रम त्रैमासिक रिपोर्ट्स ।
15. विभाग की Web site की maintenance/updation.
16. विभाग के सभी प्रभागों को वर्ष के दौरान कम्प्यूटरीकरण से सम्बन्धित सभी प्रकार का सहयोग एवं सहायता प्रदान की गई ।
17. पी.मैट (PMAT) Performance Management and Accountability Toolkit की मोनिटरिंग ।
18. ई-वितरण (हिमकोष) कार्य ।
19. ई-सर्विस बुक का कार्य ।
20. ए0सी0ए0/एस0पी0ए0 केन्द्रीय सहायता (नीति आयोग)
21. संसद सदस्यों के सॉफ्टवेयर की मोनिटरिंग ।
22. विकेन्द्रीकृत योजनाओं का सॉफ्टवेयर की मोनिटरिंग ।
23. ई-विधान का कार्य व मोनिटरिंग ।
24. राज्य वित्त आयोग के लिए सॉफ्टवेयर ।

### 3.3. जिला कार्यालय:

प्रदेश के सभी 10 गैर-जनजातीय जिलों में जिला योजना कक्षों की स्थापना की जा चुकी है। जिला योजना कक्ष जिला स्तर पर सम्बन्धित उपायुक्तों के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट को मुख्य योजना अधिकारी घोषित किया गया है । जिला योजना अधिकारी, जिला योजना कक्षों के मुखिया हैं । जिला योजना कक्षों को निम्न स्टाफ उपलब्ध करवाया गया है :-

1. जिला योजना अधिकारी
2. साख योजना अधिकारी
3. सहायक अनुसंधान अधिकारी

4. सांख्यिकीय सहायक
5. वरिष्ठ सहायक (जिला शिमला, मण्डी एवं कांगड़ा में दो-दो पद)
6. आशुटंकक
7. लिपिक
8. चपड़ासी

योजना विभाग द्वारा संचालित सभी विकेन्द्रीकृत कार्यक्रमों जैसे कि विकास में जन सहयोग, क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत नियोजन, विधायक क्षेत्र विकास निधि, मुख्यमन्त्री ग्राम पथ, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना तथा जिला ईनोवेशन फंड इत्यादि को जिला स्तर पर जिला योजना कक्षों के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय द्वारा किए जाने वाले विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के मूल्यांकन अध्ययन का कार्य एवं अन्य कार्य भी जिला योजना कक्षों के माध्यम से किये जा रहे हैं। जिला स्तर पर योजना, विकास एवं 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की त्रैमासिक बैठकों में सभी योजना कार्यक्रमों की समीक्षा एवं अनुश्रवण का कार्य भी जिला योजना कक्ष कर रहे हैं। जिला स्तर पर जिला योजना कक्ष, राज्य सरकार के विकेन्द्रीकृत योजना प्रक्रिया के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। जिला योजना अधिकारी जिला स्तर पर विभाग का जन सूचना अधिकारी है। प्रदेश सरकार की विकेन्द्रीकृत नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के सम्बन्ध में जिला योजना कक्षों की स्थापना बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है।

**सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत उप-नियम 4(1) (बी) के अन्तर्गत सूचना:**

(i)	विभाग के कार्य एवं कर्तव्य	कृपया मद् 'पृष्ठभूमि एवं परिचय' तथा 'संगठनात्मक ढांचा' का अवलोकन करें ।
(ii)	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं ड्यूटी।	<p><b><u>सलाहकार (योजना)</u></b>  विभाग का समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय नियन्त्रण सलाहकार (योजना) कार्य निष्पादन में अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) हि0प्र0 सरकार की सहायता करते हैं तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) हि0प्र0 सरकार के नियन्त्रण में कार्य करते हैं ।</p> <p><b><u>संयुक्त निदेशक (योजना)</u></b>  संयुक्त निदेशक कार्यालय अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं । वह सलाहकार (योजना) के साथ विभिन्न दायित्व निवारण एवं कार्य जैसे योजना प्रारूपण, कार्यान्वयन एवं समय-समय पर योजना आयोग भारत सरकार द्वारा प्रदत्त कार्यों के निष्पादन में कड़ी के रूप में कार्य करते हैं ।</p> <p><b><u>उप-निदेशक (योजना)</u></b>  सभी उप-निदेशक विभाग के विभिन्न प्रभागों जैसे कि योजना प्रारूपण, योजना कार्यान्वयन, योजना प्रारूपण, नाबाई, मूल्यांकन, जन-शक्ति एवं रोजगार, कम्प्यूटरीकरण, क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन, पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना, आर.एफ.डी., इत्यादि के नियन्त्रक हैं । समस्त उप-निदेशक विभाग की विभिन्न गतिविधियों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु सलाहकार (योजना) की सहायता/सहयोग करते हैं ।</p> <p><b><u>अनुसंधान अधिकारी/ जिला योजना अधिकारी</u></b>  विभाग के विभिन्न प्रभागों के नियन्त्रण में उप-निदेशकों की सहायता करते हैं । सभी नस्तियां उनके माध्यम से उप-निदेशकों को भेजी जाती हैं । जिला योजना अधिकारियों को उपलब्ध करवाया गया स्टाफ एवं उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख <b>मद्-3.3. "जिला कार्यालय"</b> में किया गया है ।</p> <p><b><u>सहायक अनुसंधान अधिकारी</u></b>  विभिन्न कार्यों, प्रस्तावों एवं पत्राचार अभिमत के उपरान्त अनुसंधान अधिकारियों को आगामी उच्च स्तर का निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत करते हैं ।</p> <p><b><u>सांख्यिकीय सहायक</u></b>  विभिन्न कार्यों, प्रस्तावों एवं पत्राचार अभिमत के उपरान्त अनुसंधान अधिकारियों को आगामी उच्च स्तर का निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत करते हैं ।</p> <p><b><u>गणक</u></b>  विभाग के विभिन्न प्रभागों में कार्यरत हैं तथा अनुसंधान अधिकारियों द्वारा जो कार्य उन्हें सौंपे जाते हैं उनका निष्पादन करते हैं ।</p>

		<p><b><u>प्रोग्रामर</u></b>          प्रोग्रामर कम्प्यूटर कक्ष के प्रभारी हैं । वह योजना विभाग के कम्प्यूटरीकरण के कार्य, जैसे कि सॉफ्टवेयर तैयार करना, इत्यादि में सहायता करते हैं ।</p> <p><b><u>कार्यक्रम योजना अधिकारी</u></b>          कार्यक्रम योजना अधिकारी विभाग में कम्प्यूटरीकरण के कार्य, जैसे कि सॉफ्टवेयर तैयार करने में प्रोग्रामर की सहायता करते हैं ।</p> <p><b><u>संगणक संचालक</u></b>          गणक संचालक विभाग में कम्प्यूटरीकरण के कार्य को सुचारु रूप से चलाने हेतु कार्यक्रम योजना अधिकारी/ प्रोग्रामर तथा विभिन्न प्रभागों की सहायता करते हैं ।</p> <p><b><u>अधीक्षक ग्रेड-1</u></b>          अधीक्षक वर्ग-1 योजना विभाग के प्रशासनिक कक्ष के समस्त प्रशासनिक कार्यों को निष्पादित करते हैं । प्रशासन प्रभाग की सभी नस्तियाँ प्रशासनिक प्रस्तावों सहित अधीक्षक वर्ग-11 अधीक्षक वर्ग-1 के माध्यम से उच्च स्तर पर निर्णय हेतु प्रस्तुत करते हैं ।</p> <p><b><u>अधीक्षक ग्रेड-11</u></b>          अधीक्षक ग्रेड-11 प्रशासन कक्ष में कार्यरत सभी कर्मचारियों के कार्यों पर नजर रखते हैं, तथा प्रशासन कक्ष के सभी सहायक अपनी-अपनी नस्तियाँ प्रशासनिक प्रस्तावों सहित अधीक्षक वर्ग-1 के आगामी निर्णय हेतु अधीक्षक वर्ग-11 के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं ।</p> <p><b><u>वरिष्ठ सहायक/ कनिष्ठ सहायक</u></b>          विभाग की स्थापना से सम्बन्धित मामलों को अधीक्षक वर्ग-11 के माध्यम से उच्च स्तर पर अन्तिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करते हैं ।</p> <p><b><u>लिपिक</u></b>          यह प्रशासन प्रभाग में कार्यरत हैं तथा अधीक्षक वर्ग-1 आहरण एवं विरतण अधिकारी / अधीक्षक वर्ग-11 द्वारा सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करते हैं ।</p> <p><b><u>निजि सहायक/वरिष्ठ आशुलिपिक/कनिष्ठ आशुलिपिक</u></b>          ये कर्मचारी विभागाध्यक्ष, संयुक्त निदेशक एवं उप-निदेशकों के साथ श्रुतलेख/टंकण कार्य/टैलीफोन काल सुनने के लिए कार्यरत हैं तथा विभाग की गोपनीय किस्म की नस्तियों एवं अभिलेखों का रख-रखाव करते हैं ।</p> <p><b><u>आशु-टंकक</u></b>          जिला योजना अधिकारियों के साथ श्रुतलेख/टंकण कार्य/टैलीफोन काल सुनने / इत्यादि कार्यों के लिए कार्यरत हैं । जिला योजना अधिकारियों द्वारा सौंपे गए सभी प्रकार के कार्य करते हैं ।</p> <p><b><u>प्रतिलिपि यन्त्र चालक</u></b>          विभाग की फोटोस्टेट मशीनों का संचालन करते हैं ।</p>
--	--	---

		<p><b>चपड़ासी</b> विभाग की डाक, नस्तियों को लाना व ले जाना, टेबल इत्यादि की सफाई तथा कार्यालय मेनुअल के अनुरूप कार्य करते हैं ।</p> <p><b>चौकीदार</b> विभाग के सभी कमरों पर प्रतिदिन सायं छुट्टी के उपरान्त निगरानी/देखरेख रखते हैं ।</p> <p><b>सफाई कर्मचारी</b> विभाग के कमरों, वरामदों, शौचालयों एवं वास वेशनों की सफाई हेतु नियुक्त हैं ।</p>
(iii)	प्रतिबद्धता एवं परिवेक्षण हेतु निर्णय प्रक्रिया के लिए अपनाई गई विधि एवं माध्यम	सलाहकार (योजना) विभागाध्यक्ष हैं तथा उनमें विभागाध्यक्ष की सभी शक्तियां निहित हैं । विभाग के विभिन्न अधिकारी विभागीय कार्यों को निपटाने एवं उचित निर्णय लेने हेतु विभागाध्यक्ष की सहायता करते हैं । विभागाध्यक्ष विभाग के विभिन्न अधिकारियों को कार्य सौंपते हैं। विभाग की नस्तियां प्रभागाध्यक्षों के माध्यम से अन्तिम निर्णय हेतु सलाहकार (योजना) को प्रस्तुत की जाती है ।
(iv)	कार्य निष्पादन हेतु मापदण्ड	विभाग के भिन्न-2 कार्य विभिन्न स्तर पर सरकार द्वारा समय-2 पर निर्धारित नियमों/ नितियों एवं शक्तियों के अनुसार निष्पादित किए जाते हैं ।
(v)	नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली एवं अभिलेख जो विभाग में हैं अथवा इनके नियन्त्रण या इसके कर्मचारियों द्वारा कार्यों के निष्पादन हेतु प्रयोग किए जा रहे हैं ।	<p>विभाग में प्रयोग किए जा रहे नियमों-विनियमों, निर्देशों नियमावली का संक्षिप्त विवरण निम्न है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. सी.सी.एस. लीव रूलज, 1972</li> <li>2. सी.सी.एस. एण्ड सी.सी.ए रूलज</li> <li>3. एच.पी.एफ.आर रूलज</li> <li>4. एच.पी.एफ.आर एण्ड एस आर रूलज</li> <li>5. मैडिकल एटैन्डेंस सुविधा नियम</li> <li>6. गृह निर्माण अग्रिम रूलज</li> <li>7. यात्रा अवकाश रूलज</li> <li>8. बजट मेनुअल</li> <li>9. आफिस मेनुअल</li> <li>10. पेंशन नियम</li> <li>11. सामान्य भविष्य निधि नियम</li> </ol> <p><b>निम्नलिखित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देश:-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. विकेन्द्रीकृत नियोजन</li> <li>2. विकास में जन सहयोग कार्यक्रम</li> <li>3. क्षेत्रीय विकास निधि योजना</li> <li>4. मुख्यमन्त्री ग्राम पथ योजना</li> <li>5. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना</li> <li>6. पिछड़ा क्षेत्र उप योजना</li> <li>7. बाहया सहायता परियोजना प्रभाग</li> <li>8. ग्रामीण संरचना विकास निधि</li> <li>9. जिला इनोवेटिव निधि (District Innovative Fund)</li> </ol>

		अधिकारी/ कर्मचारी सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों जिन्हें योजना विभाग की वैबसाईट पर डाला गया है का प्रयोग कर सकते हैं । विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन जिसमें संगठनात्मक ढांचा भी दिया गया है को विभाग की वैबसाईट पर डाल दिया गया है
(vi)	दस्तावेजों का विवरण जोकि विभाग में हैं या इसके नियन्त्रण में हों।	पंच-वर्षीय योजना/ वार्षिक योजना, भिन्न-भिन्न योजना कार्यक्रमों का मूल्यांकन अध्ययन, जनशक्ति एवं रोजगार पर फैक्ट बुक, पंच-वर्षीय योजना मध्यकालीन समीक्षा, विधायक प्राथमिकता योजनाओं की सूची, जिलावार त्रैमासिक 20-सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन रिपोर्ट एवं विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट ।
(vii)	किसी नीति को बनाने या कार्यान्वित करने हेतु लोक सदस्यों के साथ विचार-विमर्श के सम्बन्ध में कोई विवरण हो तो ।	विभाग की विभिन्न समितियों में जन-प्रतिनिधियों को गैर-सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है । गैर-सरकारी सदस्य समितियों की बैठकों में सरकार की नीति-निर्धारण के लिए बहुमूल्य सुझाव देते हैं । इसके अतिरिक्त योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा में भी जन-प्रतिनिधि बैठकों के माध्यमों से भाग लेते हैं । हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड, राज्य/जिला/उप-मण्डल स्तर की योजना विकास एवं 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समितियों में गैर-सरकारी सदस्यों को मनोनीत किया जाता है । इसके अतिरिक्त राज्य की वार्षिक योजना की प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए समस्त विधायकों एवं राज्य से सम्बन्धित सांसदों के साथ बैठकों के माध्यम से विचार-विमर्श किया जाता है । उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से राज्य के नीति-निर्धारण, योजनाओं के कार्यान्वयन, समीक्षा एवं अनुश्रवण में जन-प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है ।
(viii)	बोर्ड, कौंसिल, कमेटियां एवं अन्य निकाय/ सभाओं का गठन जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति परामर्श हेतु शामिल हों तथा इनकी बैठकें लोगों के लिए खुली हों या बैठकों की कार्यवाही लोगों की पहुंच में हो।	विभाग में निम्नलिखित बोर्ड/कमेटियों का गठन किया गया है:- <ol style="list-style-type: none"> <li>1. हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड ।</li> <li>2. राज्य/जिला/उप-मण्डल स्तरीय योजना विकास एवं 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समितियां ।</li> </ol> <p>इन बोर्ड/कमेटियों की बैठकें आम लोगों के लिए खुली नहीं होती हैं फिर भी आवेदन करने पर बैठकों की कार्यवाही रिपोर्ट की प्रति लोग ले सकते हैं ।</p>
(ix)	विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका ।	कृपया मद्- '2. योजना विभाग-स्टाफ स्थिति' का अवलोकन करें
(x)	प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा लिया जाने वाला मासिक परिश्रमिक तथा नियम प्रणाली ।	सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित वेतनमानों के आधार पर सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ते प्रदान किए जाते हैं ।
(xi)	प्रत्येक एजेंसी का बजट आवंटन जिसमें सभी योजनाओं का विवरण तथा व्यय प्रस्ताव एवं	योजना विभाग द्वारा त्रैमासिक आधार पर योजना स्कीमों एवं विकेन्द्रीकृत कार्यक्रमों के लिए सम्बन्धित विभागों एवं उपायुक्तों को धन का आवंटन प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं निर्धारित माप-दण्डों के आधार पर किया जाता है । प्रभाग वार उद्देश्य, कार्यक्रम,

	आहरण की रिपोर्ट जो बनती है ।	आबंटन, व्यय, इत्यादि का विस्तृत उल्लेख सम्बन्धित प्रभागों के विवरण में किया जा चुका है ।
(xii)	उपदान कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका जिसमें लाभभोगियों का विवरण धनराशि सहित ।	विभाग द्वारा सीधे तौर पर कोई उपदान कार्यक्रमों का निष्पादन नहीं किया जाता है ।
(xiii)	रियायतों के पात्रों का विवरण ।	लागू नहीं है ।
(xiv)	इलैक्ट्रॉनिक्स तरीके से सूचना उपलब्धता बारे ।	विभाग की वेबसाइट बनाई गई है । विभिन्न कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचना विभाग की वेबसाइट <a href="http://www.hp_planning.nic.in">www.hp_planning.nic.in</a> पर उपलब्ध है।
(xv)	लोगों/नागरिकों की सुविधा के लिए सूचना प्राप्त करने हेतु लाइब्रेरी या वाचनालय का प्रावधान हो तो उसका विवरण जिसमें समय का विवरण भी हो ।	विभाग के मुख्यालय एवं जिलों से सम्बन्धित कोई भी सूचना विभाग के कार्यालयों से 10.00 से 5.00 बजे सायं तक, रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर, प्राप्त की जा सकती है ।
(xvi)	लोक सूचना अधिकारियों के पद-नाम एवं विवरण ।	सूचना अगले पृष्ठ पर दी गई है ।
(xvii)	ऐसी अन्य कोई सूचना हो तथा हर वर्ष अपडेट की जानी हो ।	लागू नहीं है ।



योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश के सहायक लोक सूचना अधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों एवं अपील प्राधिकारी का विवरण ।

क्रम सं०	प्राधिकारी का नाम (जैसे कि सहायक लोक सूचना अधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों एवं अपील प्राधिकारी)	पदनाम	पता दूरभाष सहित	क्षेत्राधिकार / युनिट जिसके अन्तर्गत उनके नियन्त्रण में प्रार्थी को सूचना देनी अपेक्षित है
1.	2.	3.	4.	5.
<b>(क) सचिवालय स्तर पर</b>				
1.	श्री रिखी राम लोक सूचना अधिकारी	उप-सचिव (योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार	आर्मजडेल बिल्डिंग, हि०प्र० सचिवालय, शिमला-2 दूरभाष नं. 2628504	सचिवालय स्तर पर योजना विभाग
2.	डॉ० श्रीकान्त बाल्दी अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त मुख्य सचिव, (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार	आर्मजडेल बिल्डिंग, हि०प्र० सचिवालय, शिमला-2. दूरभाष नं. 2620043	सचिवालय स्तर पर योजना विभाग
अधिसूचना संख्या: पीएलजी.ए (3) 4/2005 दिनांक 27-06-2009 सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005 (एक्ट नं. 22 ऑफ 2005) के सैक्शन 5 एवं 9 के अन्तर्गत ।				
<b>(ख) राज्य स्तर पर</b>				
1.	श्री दिवान चन्द लोक सूचना अधिकारी	अधीक्षक ग्रेड-1	योजना भवन, हि०प्र० सचिवालय, शिमला-2 दूरभाष नं. 2629471	राज्य स्तर पर योजना विभाग
2.	श्री भाग सिंह ठाकुर, सहायक लोक सूचना अधिकारी	अधीक्षक ग्रेड-II	योजना भवन, हि०प्र० सचिवालय, शिमला-2 दूरभाष नं. 2880371	राज्य स्तर पर योजना विभाग
3.	श्री अक्षय सूद, अपील प्राधिकारी	सलाहकार (योजना)	योजना भवन, हि०प्र० सचिवालय, शिमला-2 दूरभाष नं. 2621698	राज्य स्तर पर योजना विभाग
अधिसूचना संख्या: पीएलजी.ए (3) 4/2005 दिनांक 22-12-2005 सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005 के सैक्शन 5 एवं 9 के अन्तर्गत ।				

क्रम सं०	प्राधिकारी का नाम (जैसे कि सहायक लोक सूचना अधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों एवं अपील प्राधिकारी)	पदनाम	पता दूरभाष सहित	क्षेत्राधिकार / युनिट जिसके अन्तर्गत उनके नियन्त्रण में प्रार्थी को सूचना देनी अपेक्षित है
1.	2.	3.	4.	5.
<b>(ग) जिला स्तर पर</b>				
1.	श्री तारा चन्द चौहान, लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय शिमला दूरभाष नं.0177-2808399	सम्बन्धित जिला
2.	श्री प्रदीप कुमार पुर्ला, लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय सोलन दूरभाष नं.01792-220697	सम्बन्धित जिला
3.	श्री अजुज कुमार, लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय जिला सिरमौर स्थित नाहन दूरभाष नं.01702-223008	सम्बन्धित जिला
4.	श्री गौतम चन्द, लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय चम्बा दूरभाष नं.01975-226057	सम्बन्धित जिला
5.	श्री रविन्द्र कटोच, लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय कांगड़ा स्थित धर्मशाला दूरभाष नं.. 01892-223316	सम्बन्धित जिला
6.	श्री कुलदीप सिंह लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय मण्डी दूरभाष नं.01905-225212	सम्बन्धित जिला
7.	श्री विनोद कुमार लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय ऊना दूरभाष नं.01899-226166	सम्बन्धित जिला
8.	श्रीमती मुक्ता ठाकुर, लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर दूरभाष नं.01978-222668	सम्बन्धित जिला
9.	श्री तेज सिंह ठाकुर, लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय कुल्लू दूरभाष नं.01902-222873	सम्बन्धित जिला
10	श्री राजीव कुमार, लोक सूचना अधिकारी	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय हमीरपुर दूरभाष नं. 01972-222702	सम्बन्धित जिला
अधिसूचना संख्या: पीएलजी.ए (3) 4/2005 दिनांक 22-12-2005 सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005 के सैक्शन 5 एवं 9 के अन्तर्गत ।				

\*\*\*\*\*

*(FOR OFFICE USE ONLY)*



**ANNUAL**  
**GENERAL ADMINISTRATIVE**  
**REPORT**  
**2016-2017**

**Planning Department**  
**Government of Himachal Pradesh**  
**Shimla-171002**

## CONTENTS

<b>Sr. No.</b>	<b>Subject</b>	<b>Page No.</b>
1.	BACKGROUND AND INTRODUCTION	1
2.	STAFF POSITION – PLANNING DEPARTMENT	1-2
3.	ORGANIZATIONAL STRUCTURE	2
3.1.	STATE PLANNING BOARD	2-4
	HEADQUARTERS	4
	(I) Administration Division	5
	(II) Plan Formulation Division	5-6
	(III) Plan Implementation Division	6-8
	(IV) Backward Area Sub Plan (BASP) Division	8-9
	(V) Regional & District Planning Division	9-14
	(VI) Manpower and Employment Division	15
3.2.	(VII) Externally Aided Project (EAP)/Innovation Division	15-20
	(VIII) Skill Development	20
	(IX) NABARD – RIDF Division	21-24
	(X) 20-Point Programme-2006 Division	24-27
	(XI) Railway Division	28-29
	(XII) Evaluation Division	29
	(XIII) MLA Priority Division	29-30
	(XIV) Computerization Division	30
3.3.	DISTRICT OFFICES	31
4.	INFORMATION OF RTI ACT-2005	32-39

## 1. BACKGROUND AND INTRODUCTION:

The State Planning Department has been mandated to formulate Five Year and Annual Plans, determine the State Plan priorities, fixing of plan size, earmarking of funds for various schemes, etc. The other activities consist of Project Appraisal of Externally Aided Projects, Implementations of scheme under RIDF funded by NABARD, Monitoring of Plan Schemes, Decentralization of Planning process, Evaluation of Schemes, Man Power Planning, Implementation of Backward Area Sub-Plan, Review of 20-Point Programme, works related to construction of rail lines and allied works in HP, etc.

## 2. STAFF POSITION - PLANNING DEPARTMENT:

Sr. No.	Category	Sanctioned Posts	Filled-up	Vacant
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Chairman Employment Generation & Resources mobilization	1	1	0
2.	Chairman (20 Point Programme)	1	1	0
3.	Dy. Chairman, State Planning Board	1	1	0
4.	Adviser (Planning)	1	1	0
5.	Joint Director	1	1	0
6.	Deputy Directors	6	6	0
7.	Research Officers / District Planning Officers	20	19	1
8.	Credit Planning Officers	10	10	0
9.	Assistant Research Officer	17	13	4
10.	Statistical Assistant	21	11	10
11.	Computer	6	4	2
12.	System Analyst	1	0	1
13.	Programmer	1	1	0
14.	Programme Planning Officer	2	2	0
15.	Computer Operators	1	0	1
16.	Private Secretary	1	1	0
17.	Personal Assistant	2	1	1
18.	Senior Scale Stenographer	1	1	0
19.	Junior Scale Stenos	6	6	0
20.	Steno-Typists	3	3	0
21.	Junior Office Assistant(9 against Steno & 2 against Clerk)	11	0	11
22.	Superintendent Grade-I.	1	1	0
23.	Superintendent Grade-II.	1	1	0
24.	Senior Assistant	17	17	0
25.	Junior Assistant	1	1	0

1.	2.	3.	4.	5.
26.	Clerk	13	11	2
27.	DMO	1	1	0
28.	Driver	5	5	0
29.	Peons	20	19	1
30.	Chowkidar	1	0	1
31.	Frash	1	1	0
32.	Jamadar	1	1	0
33.	Sweeper	1	1	0
	<b>TOTAL</b>	<b>177</b>	<b>142</b>	<b>35</b>

\* : Pay and allowances of Deputy Chairman, State Planning Board and Chairman, Twenty Point Programme are decided by the State Government at the time of their nomination.

### 3. ORGANISATIONAL STRUCTURE:

The organizational structure of Planning Department consists of following three tiers:-

- 3.1. State Planning Board.
- 3.2. Headquarters.
- 3.3. District Offices.

#### 3.1. STATE PLANNING BOARD:

State Planning Board was reconstituted by nominating official and non-official members on 12<sup>th</sup> Feb., 2013.

#### I. Composition:

(i) **Chairman:** Chief Minister

(ii) **Non-official Members:**

1. All Cabinet Ministers
2. All MPs (Lok Sabha and Rajya Sabha)  
(Notified separately)
3. One Representative each of Farmers,  
Industrialists Trade- SC, ST, OBC, Women  
(Notified separately)
4. Former MPs / MLAs and sitting MLAs  
(Notified separately)
5. Ex-Chief Secretaries/ Retd. Government Officers of key departments  
(Notified separately)

**(iii) Official Members:**

1. Chief Secretary,
2. All Administrative Secretaries
3. All Vice-Chancellors of Universities in Himachal Pradesh

**(iv) Ex-officio Members:**

1. President, HP Committee, PHD Chamber of Commerce & Industries
2. Officer-in-Charge of Regional Office, NABARD, Himachal Pradesh

**(v) Member Secretary : Adviser (Planning)**

**II. Terms of Appointment:** As may be prescribed by the Govt. of H.P. from time to time.

**III. Headquarters of the Board:**

The Headquarters of the State Planning Board will be in Shimla. The Board may, however, meet at any other place as and when considered necessary.

**IV. Functions:**

The functions of the Board are as under:-

- To determine the Plan priorities for State in the light of overall National objectives.
- To assess the man-power and financial resources and their organizational and institutional capabilities.
- To assess the level of development in important sectors for the State as a whole as well as for various districts and regions.
- In the light of above, formulate a long term perspective plan for the most effective and balanced utilization of State resources.
- To assist the State Government in the formulation of the five year plans and annual plans and evolve a short term strategy (Five Year Plan) for planned development after examination of different approaches so as to achieve maximum growth rate keeping in view Social justice.
- To identify factors which tend to retard the economic and social development of the State and determine conditions to be established for successful execution of the plan.
- To suggest policies and programmes for removing the imbalances prevailing in various regions in the State and to assist in the formulation of the district plans/area Plans.

- To review the progress of implementation of the plan programmes and recommend such adjustments in policies and measures as the review may indicate.
- To make critical appraisal of on-going programmes leading to a determination of the extent to which some of the identified on-going programmes of projects would need to be continued.
- To review the implementation of plan projects and other development schemes.
- To advise on the problem of unemployment and suggest ways and means for tackling it.
- To advise on such other matters connected with the economic development as may be assigned by the State Government.
- To make such interim or ancillary recommendations as appear to it to be appropriate for facilitating the discharge of duties assigned or on a consideration of the prevailing economic conditions, current policies, measures and development programmes or an examination of such specific problems as may be referred to it for advice by the State Government.
- To collect and analyse information/data regarding Plan schemes.
- To review the working of Government Corporations, Boards and suggest means for their improvement.
- To highlight difficulties being faced in the implementation of the plan schemes at district level and suggestions to overcome them.
- To evaluate various projects/corporations according to the directions of Chairman.

State Annual Plan size amounting to Rs. 5200.00 crore for the year 2016-17 was discussed and approved.

### **3.2. HEADQUARTERS:**

According to the rule of business, following is the structure of Planning Department for transaction of official business:-

1.	Minister – Incharge	Hon'ble Chief Minister, HP.
2.	Administrative Secretary	Addl. Chief Secretary (Planning) to the GoHP.
3.	Head of Department	Adviser (Planning) HP.

Adviser (Planning) is the Head of the Department. The various divisions viz. Plan Formulation, Project Formulation, Plan Implementation, Computerization, Evaluation, Manpower & Employment, Administration, Regional & District Planning, Backward Area Sub-Plan, Railways and Twenty Point Programme are functioning under the control of Adviser (Planning). These divisions are headed by Joint Director / Deputy Directors. A Joint Director / Deputy Director functions as Head of Office. The Division-wise details of goals, objectives, programmes, allocation, expenditure, etc. are given below:-



## I. ADMINISTRATION DIVISION:

The Administration Division functions under the control of Joint Director (Administration).

The Administration Division does routine Administrative and Personnel Management and other related works such as recruitment, promotion, confirmation, transfers / postings, disciplinary actions / proceedings, budget, accounts, reply of audit / CAG / PAC paras, store & stock and other miscellaneous works assigned to it. During the year under report, the Administrative Division of the department has performed the above mentioned works / duties.

## II. PLAN FORMULATION DIVISION:

### 1. Preparation of State's Draft Annual Plan (2017-18) Document

- ◆ A series of meetings with concerned departments were held in of October, 2016 under the Chairmanship of Additional Chief Secretary (Planning) to discuss the plan priorities of the departments for Annual Plan (2017-18).
- ◆ The guidelines for preparation of detailed Annual Plan document for the year 2017-18 were issued to all concerned departments requesting them to send detailed Plan proposals.
- ◆ On scrutiny of departmental proposals and analysis of data collected from departments for various heads of development, a Draft Annual Plan (2017-18) document was prepared by proposing a plan size of Rs. 5700 crore for the meeting of State Planning Board for its approval which was held on 6<sup>th</sup> February, 2017. The same has also been passed by the State Legislature. The Sector –wise break up is given as under:-

( Rs. in Crore)		
Sr. No.	Sector	Annual Plan (2017-18) Proposed Outlay
1.	2.	3.
1.	Agriculture and Allied Activities	713.66
2.	Rural Development	113.88
3.	Special Area Programme	27.78
4.	Irrigation & Flood Control	371.30
5.	Energy	682.70
6.	Industry and Minerals	118.96
7.	Transport & Communication	1073.52
8.	Science, Technology & Environment	17.37
9.	General Economic Services	267.35
10.	Social Services	2213.16
11.	General Services	100.32
	<b>Total :</b>	<b>5700.00</b>

- ◆ The Annual Plan 2017-18 has been formulated keeping in view the targets defined in the Global and National Sustainable Development Goals.
- ◆ Preliminary work on documentation of 3 year action plan, 7 year strategy and 15 year document as advocated by the NITI Aayog has been done which has been aligned with Sustainable Development Goals.
- ◆ The department has coordinated with different departments and NITI Aayog to help departments take action in accordance with the sectoral policies suggested and framed by NITI Aayog at the National level.

### **III. PLAN IMPLEMENTATION DIVISION:**

After passing of budget from Vidhan Sabha, the implementation of plan budget starts in following ways: -

1. This division examines proposals of diversion and re-appropriation received from different departments thoroughly. Keeping in view the importance and priorities of the cases, diversions/ re-appropriations are permitted.
2. Additionalities are provided from those Schemes/Heads, which have the possibility of low intensity of expenditure. A cut is imposed on such schemes in order to provide additionalities in other schemes, which are of utmost importance.
3. This division also arranges meetings with concerned departments to sort out matters of additionalities to dispose-off cases promptly.
4. During the period under report, proposals on diversions and re-appropriations were called from all departments through concerned Administrative Departments (ADs) in respect of Earmarked & Non-earmarked Sectors for scrutiny and examination.
5. During the year under report, 527 references from different departments for obtaining advice on their departmental files had been received and were examined, processed and suitably advised after obtaining prior approval of the competent authority.
6. To smoothen Plan Implementation in consonance with budget, the entire plan has been linked with budget through software for this purpose.

In addition to this, following activities were undertaken by the Plan Implementation during the period under reference:-

## **1. Quarterly Budget Allocation:-**

Quarterly Budget Authorization for the year 2016-17 was given to all departments under general plan outlay and physical and financial progress reports were collected/ compiled from the departments.

Following quarter-wise norms for Plan expenditure have been fixed:-

<b>Quarters</b>	<b>Plan Expenditure (%)</b>
<b>First</b>	20%
<b>Second</b>	25%
<b>Third</b>	30%
<b>Fourth</b>	25%
<b>Total</b>	<b>100 %</b>

## **2. Budget Assurances:**

This Division has reviewed the progress of Implementation of Budget Assurances given during the Budget Speech for 2016-17. The information from all implementing departments was collected and compiled.

## **3. Pending issues with Government of India:**

Pending issues with Government of India is a compilation of the important matters / issues which are pending with GoI. Important issues were uploaded in software developed by Cabinet Secretariat regularly for follow up through e-Samiksha.

## **4. Centrally Sponsored Schemes:**

Centrally Sponsored Schemes have a very important place in the economy of the State as these schemes supplement the State's resources. At present various Centrally Sponsored Schemes either 100% or shared in some ratio between Centre and State are in progress. This Division had advised the implementing departments on financial implications of CSS and their counterpart state provisions in plan.

## **5. United Nation Development Programme:**

As per the action plan of the Human Development Towards Bridging Inequalities (HDBI) Project, four studies were outsourced to independent agencies:-

1. Study to assess the Human Development for inclusive and sustainable Green Growth in Himachal Pradesh has been sent to an expert for reviewing.
2. Study to explore the causes of Declining Sex Ratio in the age group of 0-6 years has been finalized.

3. Financial Report Card on Human Development in Himachal Pradesh has been sent for revision after getting comments from the expert.
4. Study to assess the Socio-Economic Status of Gujjars in Himachal Pradesh was finalized after incorporating comments and suggestions from the expert.

#### **IV. BACKWARD AREA SUB-PLAN (BASP) DIVISION:**

State Government has notified the Backward Area Sub Plan for identifying and mitigation of sub-regional disparities in development on various parameters. During 1995-96, H.P. Government had framed a comprehensive policy for backward areas which is being implemented since then in Himachal Pradesh. The salient features of the policy are as under:-

- (a) The Backward Area Sub Plan comprises three categories:-
  - (i) Backward Blocks:** All blocks having 50% or more than 50% declared Backward Panchayats have been declared as Backward Blocks. Presently, there are Eight Backward Blocks in the State having 304 Backward Panchayats.
  - (ii) Contiguous Pockets:** Group of five or more declared backward panchayats having geographical contiguity have been declared as Contiguous Pockets. There are fifteen Contiguous Pockets having 133 backward panchayats in the State.
  - (iii) Dispersed Panchayats:** Other Panchayats which do not fall in the above mentioned categories (i) & (ii) have been declared as Dispersed Panchayats. There are 110 Dispersed Panchayats in the State.
- (b) Funds are earmarked for Backward Area Sub-Plan (BASP) under selected thirteen heads of development.
- (c) Both, beneficiaries and infrastructure development oriented approaches have been adopted in these areas.
- (d) The allocation of funds to districts is made in proportion to the total number of backward declared Panchayats of the district.
- (e) The Sub Plan is administered through Deputy Commissioners who can make need based diversions / re-appropriation with the approval of DPDC. Administrative and financial delegation has been given to the districts.
- (f) The Planning Department controls the Capital Heads only under BASP and Revenue Heads are operated by other concerned Departments.

There are 547 Panchayats declared as backward out of 3226 Panchayats in the State. A single Demand No-15 “Planning and Backward Area Sub Plan” has been created for separate budgetary arrangements for BASP. BASP enjoys sufficient degree of flexibility as District level Planning, Development and Twenty Point Programme Review Committee is fully authorized to decide priorities within the district. An outlay of Rs. 49.50 crore was kept for capital works under BASP for the year 2016-17 under Plan and an outlay of Rs. 54.47 crore has been provided under capital section for the year 2017-18 under BASP (Plan).

The District wise details of Backward Area Sub Plan 2016-17 outlay / expenditure of Capital Section and numbers of Backward declared Panchayats are as under:-

(Rs. in lakh)				
Sr. No.	District	Number of Backward Declared Panchayats	BASP BUDGET & EXPENDITURE 2016-17 (Capital Section)	
			Budget (Plan)	Tentative Expenditure (Plan)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Bilaspur	15	135.81	135.81
2.	Chamba	159	1439.51	1439.51
3.	Hamirpur	13	117.69	117.69
4.	Kangra	17	153.91	153.91
5.	Kullu	79	715.22	715.22
6.	Mandi	149	1348.98	1348.98
7.	Shimla	83	751.44	751.44
8.	Sirmour	26	233.12	233.12
9.	Solan	3	27.16	27.16
10.	Una	3	27.16	27.16
	<b>TOTAL</b>	<b>547</b>	<b>4950.00</b>	<b>4950.00</b>

## V. REGIONAL & DISTRICT PLANNING DIVISION:

For the implementation and monitoring of various Decentralized Planning Programmes, Regional and District Planning Division has been set up at in the Planning Department. Descriptions of the various activities of Decentralized Planning Programmes are given as under:-

### 1. Vikas Mein Jan Sahyog Programme (VMJS):

To ensure people's effective participation towards fulfilling their developmental needs in terms of infrastructure at the grass root level as well as to supplement Government's efforts / resources, the programme- Vikas Mein Jan Sahyog (VMJS) was introduced in the State from 1991-92. Under this programme, people's participation is on voluntary basis and through advance contribution in cash which is to be deposited in the Bank / Post Office accounts opened in the name of

concerned Deputy Commissioner. A budget provision of Rs.19.63 crore has been kept for the financial year 2017-18 under this scheme.

Main Salient features of this programme are given below:

1. In urban areas, cost sharing ratio between the Community and the Govt. is 50:50. While in case of Govt. assets like school buildings, health and veterinary institutions, construction of drinking water supply schemes and sewerage schemes and installation of hand pumps where the sharing pattern is in the ratio of 25:75 between Community and the Govt. This facility is only for creation of assets community and not for any family or a person/ individual assets.
2. In rural areas, cost sharing is in the ratio of 25:75 between Community and the Govt. However, in the case of tribal areas, panchayats declared as backward and areas predominantly inhabited by SCs, STs and OBCs, cost sharing is in the ratio of 15:85 between Community and the Govt.
3. Any individual can also get a public asset constructed either as a purely philanthropic nature or to commemorate the memory of his/her ancestors by sharing 50 percent cost of the work.
4. Works are required to be completed within one year from the date of sanction.
5. Community and the Govt. are liable to contribute 10% funds additionally of the cost of work for the maintenance of assets which are to be maintained.
6. All works beyond the estimated cost of Rs. 5.00 lakh are executed through the Government Departments and not by the societies/ local committees.
7. The execution of works up to Rs. 5.00 lakh are ensured under the supervision of the Assistant Engineer/ Junior Engineer of the Rural Development Department and the measurement of the work of each work done is entered in the measurement book of concerned Junior Engineer/ Technical Assistant of the area.

**The projects/assets of the following nature can be sanctioned under this programme:**

- i) Construction of buildings of Govt. Educational Institutions.
- ii) Construction of multipurpose community/public assets.
- iii) Construction of motor-able roads and rope-ways.
- iv) Construction of irrigation schemes/drinking water schemes/ installation of hand-pumps.
- v) Construction of buildings of public health services.
- vi) Provision of important missing links; such as three phases transmission lines, transformers, X-Ray plants, Ambulances etc.
- vii) Setting up of Go-Sadan for stray animals.

## **2. Sectoral Decentralized Planning (SDP):**

Sectoral Decentralized Planning Programme was started in the State during 1993-94. To maintain inter-regional development balance, distribution of funds made by the Planning Department on the basis of 60 percent weightage to population and 40 percent weightage to the area of the district as per 1981 Census. Under this programme, schemes of local needs and important missing links occurring in the budgetary allocations are mainly taken up for implementation. A budget provision of Rs. 55.07 crore has been kept for the scheme during 2017-18.

### **Salient features of this programme are given below:**

1. Under this programme schemes are sanctioned after seeking prior approval of the District-Level Planning, Development and 20-Point Programme Review Committee.
2. Only those developmental works should be considered for execution whose estimates and designs are technically approved by the competent Technical Authority / Personnel of Govt./ Semi Govt./ Govt. undertakings within the delegated technical powers. The Technical Officer / Authority, who can technically approve the estimates is competent to assess the work and authorize disbursement of payments.
3. The Deputy Commissioners are competent to accord A/A & E/S under SDP subject to the availability of budgetary provisions under selected heads of development and fulfillment of other requirements.
4. Under SDP, neither recurring expenditure / liability can be created nor bunching of sanctions and phasing of work beyond one financial year is allowed. Also, revision of estimates and revision of sanctions are not allowed.
5. The developmental works to be executed under SDP should lead to a community benefit which consist of at least five families. No works benefiting individuals/single family can be taken up under this programme.
6. Under SDP works sanctioned are required to be completed within the same financial year or within one year from the date of sanction. The phasing of work and financial sanction for more than one financial year is not permissible.

## **3. Vidhayak Kshetra Vikas Nidhi Yojana (VKVNY) :**

To strengthen the decentralization process, the State Government has started a scheme “**Vidhayak Kshetra Vikas Nidhi Yojana**” from 1999-2000. This scheme was discontinued in the year, 2001-2002 but restarted in 2003-04 with a budget provision of Rs. 24.00 lakh per constituency. The State Government has been increasing budget provision under this scheme from year to year and a provision of Rs. 1.00 crore per constituency was made in 2016-17. Now, it has been increased to Rs. 1.10 crore in the current financial year i.e. 2017-18 per constituency.

The implementation and monitoring of the scheme is done with the direct and active involvement of MLAs. The scheme has ensured balanced development of all areas in the state. A budget provision of Rs. 74.80 crore has been kept for this scheme during 2017-18.

**The scheme/works of the following nature can be under-taken under this programme:-**

- (1) Construction of rooms in Educational Institutions.
- (2) Construction of Ayurvedic Dispensaries, Veterinary Institutions & Health Sub- Centres etc.
- (3) Installation of Hand Pumps.
- (4) Construction of Motorable / Jeepable link roads in rural areas.
- (5) Construction of Community Bhawans which can be used for different institution or celebration at village level.
- (6) Provision of apparatus in Health Institutions which are not already available there such of as X-Ray Plants, Ultra Sound machines and ECG machine etc.
- (7) Purchase of Ambulance for Health Institutions subject to the condition that concerned institution/ department should have full provision for recurring expenditure on it.
- (8) Construction of small bridge/ culverts on rural roads and foot bridges on different khads, streams etc.
- (9) Construction of metalled rural paths (concrete based or black or black topped), on which two wheeler vehicles could be plied.
- (10) Water supply schemes for left out hamlets where there is necessity of public taps by providing additional pipes.
- (11) Irrigation schemes at local level.
- (12) Construction of Toilets in schools and construction of Public toilets & bathrooms in the bus stands.
- (13) Electrification of left out houses in remote/ rural areas (LT Extensions).
- (14) Maintenance of school buildings and construction of School play grounds.
- (15) Construction of Gym centre in Panchayats & urban areas.
- (16) Construction and maintenances of Bus Stands.
- (17) In rural and urban areas, maintenance of Government buildings such as Ayurvedic dispensaries, Veterinary dispensaries, Health Institutions, Community Bhawan, Education Institutions etc.
- (18) Repair and maintenance of roads in rural and urban areas.
- (19) WiFi facilities (Non-recurring expenditure).



- (20) Sanction of various facilities in public offices like sitting arrangements for students in the schools, sports kits/equipments in schools, beds and blankets in the hospitals, replacement of motor pumps of water supply and grant to Mahila Mandals for purchase of utensils (Maximum Rs. 20,000/- per Mahila Mandals) and furniture etc.

#### **4. Mukhya Mantri Gram Path Yojana (MMGPY):**

In order to provide connectivity to villages from nearby motorable roads, Kuchha Paths in rural areas are made Pucca. Besides this, construction of small culverts/ bridges for providing all weather connectivity to the people residing in far flung areas. The State Government has permitted construction of jeepable / tractorable link roads upto 2.00 km owing to hilly and difficult geographical areas. Mukhya Mantri Gram Path Yojna was launched during the year 2002-03 in the Pradesh for non-tribal areas. During the year 2004-05, this scheme was discontinued and was restarted in 2008-09. During 2015-16, a provision of Rs 5.50 crore was made to Deputy Commissioners of 10 Non-Tribal Districts under this programme. A budget provision of Rs. 5.50 crore has been made for the scheme during 2017-18.

**Main Salient features of this programme are given below:**

1. Under this scheme, allocation of funds to the districts is made on the basis of total rural population and total number of inhabited villages in the district on 50:50 ratios as per 1991 census.
2. Under the programme neither recurring expenditure / liability can be created nor construction of kutch path is allowed.
3. The works executed out of this scheme fund will be maintained by the concerned Panchayats from their own resources / revenue. Affidavit to this effect is to be obtained from the concerned Panchayats before the sanction of work.
4. Only those developmental works should be considered for execution where estimates and designs are technically approved by the Rural Development Department J.E./A.E./XEN according to their technical powers.
5. Under this programme the schemes / works to be implemented are to be approved by the District Level Planning, Development and 20-Point Programme Review Committee.

6. The works are to be completed within the sanctioned amount and no additional / revised sanction of funds will be allowed.
7. The road alignment should be got approved from the PWD, so that the Jeepable roads can be later on upgraded into normal Bus roads, as per the PWD norms.

**5. Member of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS):**

Member of Parliament Local Area Development Scheme was started in 1993-94 by Govt. of India. Under this scheme, MPs recommend works of developmental nature to be taken up in their constituencies and also of national priorities viz. drinking water, primary education, public health, sanitation and roads, etc. The sanction orders are issued by the Deputy Commissioner. Rs 5.00 crore per MP per annum is allowed to be released by Government of India for various works on the recommendations of the MP.

Following Sector schemes are eligible under MPLADS.

1. Drinking Water Facility.
2. Education.
3. Electricity Facility.
4. Health & Family Welfare.
5. Irrigation Facilities.
6. Non Conventional Energy Sources.
7. Other Public Facilities.
8. Railways, Roads ,Pathways and Bridges.
9. Sanitation and Public Health.
10. Sports.
11. Works relating to Animal Husbandry, Dairy and Fisheries.
12. Works relating to Agriculture.
13. Works relating to Cluster Development for Handloom Weavers.
14. Works relating to Urban Development.

## **VI. MANPOWER AND EMPLOYMENT DIVISION:**

The following main tasks have been assigned and performed by Manpower and Employment Division

### **i) *Fact Book On Manpower.***

Manpower and Employment Planning is an integral part of development planning. It is imperative to build up a manpower information system at State level so as to cover various aspects of technical and educated manpower. Keeping in view the importance of this information system, Manpower Division of Planning Department, H.P. brings out a comprehensive compendium of manpower information and is assigned with the work relating to the collection, compilation and tabulation of data on manpower and brings out a publication “**Fact Book on Manpower**”.

The work relating to this publication is of continuous nature requiring periodic follow-up and revision. In this publication, data with statistical tables regarding population, manpower, employment, unemployment, training and health institutions, directly related to the training and employment is compiled.

### **ii) *Employment Market Information Programme.***

Under the Employment Market Information Programme, data is collected by the Manpower division from all the District/Regional Employment Exchanges of the State which are brought out annually in a report titled the “**Quick Estimates of Employment in the Organized Sector**”. The data presented in this report covers the employment status of public and private sector establishments which existed at the end of each quarter.

## **VII. EXTERNALLY AIDED PROJECT (EAP) DIVISION:**

Externally Aided Project (EAP) Division in the Planning Department has been assigned the task of analyzing the project proposals of different departments submitted for seeking funding from external agencies. These project proposals are examined keeping in view the technical, administrative, managerial and financial aspects in relation to the socio-economic coverage and overall resource position of the State. Besides this, the division also reviews and monitors the physical and financial progress of all the EAPs being implemented in the State. This division serves as single window for the different donors for identification, appraisal and feed back in respect of EAPs. Administrative Secretary (Planning), Government of HP has been declared as State Nodal Officer for all Externally Aided Projects (EAPs) in Himachal Pradesh. Financial and physical progress of ongoing EAPs are obtained from implementing agencies on quarterly basis for ensuring its smooth implementation. Advices are given to the different departments in the context of Externally Aided Project proposals.

The Guidelines received from various external aid agencies like World Bank, ADB, JICA, GIZ, AFD & KfW, NDB etc. and Government of India were circulated

to the concerned departments to formulate the project proposals. Project proposals received from the departments were analyzed / appraised in the division keeping in view the Technical, Administrative, Managerial, Financial, Social & Economic parameters.

### **Externally Aided Projects implemented in Himachal Pradesh during 2016-17:**

(Rs. in Crore)

Sr. No.	Name of the Project	Donor Agency	Nodal Department	Total Cost	Project Period		Remarks
					Starting Date	Concluding Date	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	HP State Road Project	World Bank	Public Works	1802.84	Jul-07	Jun-16	
2	HP Mid Himalayan Watershed Development Project	World Bank	Forest	661.44	Oct-05	Mar-17	
3	Swan River Integrated Watershed Management Project	JICA	Forest	227.31	Mar-06	Mar-16	Completion of wrap-up activities
4	Infrastructure Development Investment Programme for Tourism in HP	ADB	Tourism	428.22	2010	2020	
5	HP Crop Diversification Promotion Project	JICA	Agriculture	321	Jul-11	Mar-18	
6	HP Clean Energy Transmission Investment Program	ADB	Power	1927	Jan-12	Dec-18	
7	Power Projects	ADB	Power	6673.87	Nov-08	Jun-16	
8	HP Forest Eco-System Climate Proofing Project	KfW	Forest	308.45	Apr-15	Mar-22	
9	HP Horticulture Development Project	World Bank	Horticulture	1134.00	Aug-16	Jul-23	
<b>Total</b>				<b>13484.13</b>			

**Status of some new Externally Aided Projects:-** Besides ongoing projects, following new projects have been started/are likely to be started in near future:

#### **1. WB assisted National Hydrology Project:**

National Hydrology Project PIP has been approved under four heads amounting to Rs. 70.00 crores for the period of 8 years initially from 2015-16 to 2019-20 for NHP. Under this project, it is proposed to strengthen the hydrometeorological network of the state by automation of the existing stations and setting up of new stations in the entire state and additional river basins. An outlay of Rs. 3.00 crore has been proposed for the financial year 2017-18.

## **2. ADB assisted HP Skill Development Project:**

Integrated Skill Development Project of Himachal Pradesh amounting to Rs. 640.00 crore has been approved for funding from Asian Development Bank. The duration of this project will be five years. The focus of the project is to upgrade the skill of the youth of the State in order to enhance employability and employment opportunities for the unemployment youth. All the activities under this project will be implemented by HP Kaushal Vikas Nigam established under the administrative control of Planning Department. An outlay of Rs. 1.40 crore has been proposed for the financial year 2017-18.

**3. WB assisted Integrated Financial Management System Project:** This project of financial management will be executed at State level by Treasury, Accounts and Lotteries Department. An outlay of ₹10.00 crore has been proposed for this project for the financial year 2017-18.

Some other projects of Urban Sector related to sewerage system & solid Waste processing plants & development of land fill sites and that of Rural Water Supply sector etc. are also in the pipeline for negotiations with the GoI and donor agencies at various stages and are likely to be started in near future.

## **INNOVATION AT STATE LEVEL:**

With the pledge to transform Himachal Pradesh into an Innovative State and to promote innovation through sharing of experiences across various sectors within State and to encourage departments to try new initiatives, following initiatives are being taken by State Government:

**I. Constitution of State Innovation Council (SInC):** State Innovation council was constituted by the Government of Himachal Pradesh on 7<sup>th</sup> January, 2011 under the Chairpersonship of Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh, giving representation to Administrative Secretaries of the concerned departments and Vice-Chancellors of the Universities in the State. The scope of SInC has been enlarged on 4<sup>th</sup> August, 2014 and subsequently on 31<sup>st</sup> December, 2015 by bringing in a few more institutes viz. NIT Hamirpur, Central University and IIT Mandi, HP State Council for Science, Technology & Environment alongwith Industries Department within the purview of SInC.

**II. State Innovation Fund:** With a view to promote innovation by encouraging departments to try new initiatives, State Innovation fund was instituted by State Government in 2013-14 and innovative projects of various departments are being funded subject to the availability of funds under this Fund as per guidelines.

**Innovative Ideas funded through State Innovation Fund:** Nine schemes/projects of various Departments amounting to about Rs. 2.24 crore have already been funded in the past years. For 2016-17, a budgetary provision of Rs. 1.10 crore was made

under this Fund and following five innovative projects have been approved for funding:

**a. Implementation of the first phase of the automation of Allotment & Administrative wing of HIMUDA:** This automation project aims at developing web based system to integrate & centralize various activities of HIMUDA enabling efficient exchange of information between field offices & head office and also to automate its processes with a view to provide better facilities to their clients and will result in sophisticated Management Information System (MIS). An amount of Rs. 25.00 Lakh has been sanctioned for the implementation of this project in September, 2016 from State Innovation Fund.

**b. Developing a prototype of continuous garbage collecting mechanism collecting garbage without any intervention or wastage of time:** This project of Structural Engineering Department of NIT Hamirpur aims at developing a prototype of continuous garbage collecting mechanism collecting garbage without any intervention or wastage of time having an inbuilt dustbin fitted with polybag for easier garbage disposal. An amount of Rs. 1,08,000/- has been sanctioned from State Innovation Fund for the implementation of this project in October, 2016.

**c. Development of Modern State-of-the-Art Digital Forensic Facilities in Forensic Science Laboratories in HP of RFSL, Mandi:** The proposal involves developing prototype tools for developing intensity range enhancement & de-noising methods for image and video enhancement, geometric scene analysis through single view metrology and speaker identification & recognition methods, speech enhancement etc. The solutions to these problems would be useful and directly applicable in actual practice of digital forensics. For the implementation of the said project, an amount of Rs. 16,80,000/- has been approved for funding from State Innovation Fund.

**d. Setting up of video conferencing facility at RFSL, NR, Dharamshala:** A proposal for setting up of video conferencing facility at RFSL-NR, Dharamshala amounting to Rs. 7.00 lakh has been approved for funding from State Innovation Fund for acquiring infrastructure for setting up this facility which will improve the service delivery system of the Forensic Department through connectivity with different courts of HP and would save precious time of the experts spent in journeys undertaken to depose experts testimonies at different courts across the state.

**e. Setting-up of Mini Herbal Garden & Acupressure track in Ayurvedic Health Centre, Cheog:** A proposal for setting-up of Mini Herbal Garden & in Ayurvedic Health Centre, Cheog amounting to Rs. 1.49 lakh has been approved for

funding from State Innovation Fund with an objective to raise & conserve medicinal plants in the premises of the institute with a view to have a green & environment friendly campus and to set-up an acupuncture track in this institute for helping patients in releasing tension, increases circulation, reduces pain and develops spirituality and vibrant health

### **III. HP State Innovation Award Scheme for recognizing Best Innovations:**

HP State Innovation Award Scheme was started from 2014-15 for recognizing & rewarding the innovative ideas by providing financial incentives to best innovations of identified sectors of Agriculture & Horticulture, Food Processing & Manufacturing, Academic, Social Development and Government Sectors.

**Innovations awarded for 2015-16:** For the year 2015-16, following five innovations of various sectors were awarded by Hon'ble Chief Minister, HP in State level function held on 15<sup>th</sup> April, 2017:

- 1. Innovation awarded in Agricultural & Horticulture Sector:** Dr. Kamal Sharma & Dr. Sanjeev Thakur of Dr. YS Parmar University of Horticulture & Forestry have been awarded for developing a **high yielding varieties of climate resilient species of commercial crop Harar** with early bearing technology and improved genotypes for economic cultivation in monkey inhabited areas. The pre-fruit bearing period of these high yielding strains/varieties has been reduced from 10-12 years to just 3 years and is suitable in frost affected areas, marginal lands & areas rendered uncultivated due to monkey menace & threats from stray cattle.
- 2. Innovation awarded in Social Development Sector:** Dr. Sudhir Sharma, Associate Professor, Department of Neurology, IGMCH, Shimla has been awarded under this sector for devising a simple way through his **Tele-stroke Project** to provide first aid treatment in ischemic stroke even at far off Health Institution of the State by any trained Medical Officer without the help of a specialist by making use of social networks like whatsapp etc.
- 3. Proposal under Food Processing and Manufacturing Sector:** The proposal of R.R. Enterprises related to Ready to cook spice mix products has been selected and awarded under this sector. These products save time, effort, health & money and benefits working class population, students and people staying away from home as they can spend time on productive work rather than on cooking thus making cooking easy for everyone for avoiding unhealthy junk food or packed food.
- 4. Proposal under Academic Sector:** UDAAN program started by DIET Mandi in association with District Administration, Mandi to understand the basic literacy and numeracy levels of the children of Standard 3-5 in the district with a view to

address these learning gaps by starting a learning enhancement program for them has been awarded under the said award scheme for 2015-16 in this sector.

- 5. Proposal under Government Sector: *e-Services Project*** of Town & Country Planning Department has enabled the public to access all the facilities related to planning permission during construction of houses online through web-interface. Recognizing these public friendly services and transparency & efficiency in ease of doing business in department through its e-services project, this proposal has been awarded in this sector under said scheme for 2015-16.

### **VIII. SKILL Development :**

The work relating to Skill Development is being coordinated by the Planning Department as Administrative Department in the State. During 2016-17 following activities has been taken for implementation of Skill Development activities in the State:

- Skill Development Annual Plan 2016-17 was prepared, including the proposals of concerned Departments.
- Memorandum for Skill Development Policy of Himachal Pradesh was prepared and made available to all the Administrative Secretaries and Head of the Departments for necessary action
- All necessary documents/conditions mandatory for negotiation i.e. project readiness conditions related to H.P. Skill Development Project amounting to Rs. 640 crore were completed and communicate to ADB and DEA, GOI for the release of budget after negotiation with DEA.
- Time to time meetings with consultants of Asian Development Bank and line departments were organized to speed up the implementation of Skill Development Project, under the Chairmanship of Additional Chief Secretary (Planning) / Adviser (Planning) / MD (HPKVN) during the year 2016-17.
- For the smooth functioning of Himachal Pradesh Kaushal Vikas Nigam staff on re-employment/ secondment basis was arranged. For this purpose a service committee in chairmanship of Addl. Chief Secretary of Personnel Department has been constituted.
- To link unemployed youth with employment a Skill Development Pilot Project of 1000 trainees in six Districts of HP has been started with the help of Himachal Pradesh Kaushal Vikas Nigam.
- A Skill Development Project to trained 14000 youths in 2017-18 was prepared and sent to Ministry of Skill Development and Entrepreneurship Government of India for funding. The Ministry has approved the project under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojna and sanctioned the total sum of Rs. 21, 55, 60,800 for this project.



## **IX. NABARD-RIDF DIVISION:**

Rural Infrastructure Development Fund Programmes under NABARD extending loan assistance to the State Governments for the completion of ongoing projects/ Really New Schemes in the areas of Medium and Minor Irrigation, Soil Conservation and other Rural Infrastructure Development Projects like Rural Roads and Market Yards, have been implemented since **RIDF-I (1995-96)**. This programme was continued as **RIDF-II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI & XXII** in the successive Annual Budgets. Under RIDF-I, NABARD had provided loan assistance **upto 50%** of the balance cost of ongoing projects. Later on, loan assistance was provided **upto 90% / 95%** for new eligible projects under successive RIDF tranches.

2. The State Government is availing NABARD loans under RIDF programme for a wide range of activities. Some of the activities on which the State Government has got projects approved or has posed projects to NABARD for funding are :-

- (i) Construction of Roads and Bridges.
- (ii) Construction of Irrigation schemes.
- (iii) Construction of Flood Protection Works.
- (iv) Construction of Primary School Buildings (under SBVSY).
- (v) Construction of Drinking Water Supply Schemes.
- (vi) Establishment of Citizen Information Centres.
- (vii) E-Governance.
- (viii) Construction of Science Laboratories in Senior Secondary Schools.
- (ix) Watershed Development Projects.
- (x) Strengthening of Animal Health Infrastructure.
- (xi) Production of cash crops through adoption of Precision Farming Practices (Poly Houses and Micro Irrigation).
- (xii) Diversification of Agriculture Through Micro Irrigation and related infrastructure.
- (xiii) Construction of CA Stores.

3. The NABARD has sanctioned total loan assistance of Rs. 6343 crore in favour of Himachal Pradesh upto 31<sup>st</sup> March, 2017. The tranche-wise break-up is given as under :-

(Rs. in crore)						
Sr. No	Tranche No.	Duration/Phasing Period	No. of Schemes Sanctioned	NABARD Loan Sanctioned	State Contribution	Total Amount Sanctioned
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	RIDF-I	1995-96 To 1997-98	77	14.23	4.90	19.13
2	RIDF-II	1996-97 To 1998-99	66	52.96	6.32	59.28
3	RIDF-III	1997-98 To 1999-2000	28	51.12	5.12	56.24
4	RIDF-IV	1998-99 To 2000-01	66	87.81	3.48	91.29
5	RIDF-V	1999-2000 To 2001-02	680	110.36	6.80	117.16
6	RIDF-VI	2000-01 To 2002-03	1053	127.20	10.15	137.35
7	RIDF-VII	2001-02 To 2003-04	325	168.24	8.90	177.14
8	RIDF-VIII	2002-03 To 2004-05	237	169.29	13.80	183.09
9	RIDF-IX	2003-04 To 2005-06	182	141.70	19.35	161.05
10	RIDF-X	2004-05 To 2006-07	146	91.64	9.96	101.60
11	RIDF-XI	2005-06 To 2007-08	266	224.67	29.73	254.40
12	RIDF-XII	2006-07 To 2008-09	379	272.30	36.17	308.47
13	RIDF-XIII	2007-08 To 2010-11	359	308.06	32.55	340.61
14	RIDF-XIV	2008-09 To 2011-12	136	424.82	28.13	452.95
15	RIDF-XV	2009-10 TO 2012-13	223	454.13	36.98	491.11
16	RIDF-XVI	2010-11 TO 2013-14	186	394.53	37.16	431.69
17	RIDF-XVII	2011-12 TO 2014-15	225	423.69	41.81	465.50
18	RIDF-XVIII	2012-13 TO 2015-16	164	432.16	44.32	476.48
19	RIDF-XIX	2013-14 TO 2016-17	142	496.09	65.18	561.27
20	RIDF-XX	2014-15 TO 2017-18	161	707.61	58.89	766.50
21	RIDF-XXI	2015-16 TO 2018-19	170	644.94	60.75	705.69
22	RIDF-XXII	2016-17 TO 2019-20	125	545.54	60.20	605.74
	<b>GRAND TOTAL ( I TO XXII )</b>		<b>5396</b>	<b>6343.09</b>	<b>620.65</b>	<b>6963.74</b>

4. Against the above sanctioned NABARD loan assistance of Rs. 6343 crore, the State Government has received Rs. 4465 crore upto 31.03.2017 from the NABARD. Year-wise detail of reimbursement availed under RIDF Programme from 1995-96 to 2016-17 is as under:-

Year	Reimbursement Availed (Rs. in crore)
1.	2.
1995-96	1.60
1996-97	5.31
1997-98	35.44
1998-99	40.65
1999-00	56.01
2000-01	106.92
2001-02	116.44
2002-03	141.58
2003-04	142.35

<b>Year</b>	<b>Reimbursement Availed (Rs. in crore)</b>
2004-05	83.17
2005-06	125.09
2006-07	140.38
2007-08	200.00
2008-09	220.00
2009-10	300.00
2010-11	294.49
2011-12	305.51
2012-13	400.00
2013-14	350.00
2014-15	400.00
2015-16	500.00
2016-17	500.00
<b>Total</b>	<b>4464.94</b>

5. **Project Sanction Target & Achievement (from 2006-07 to 2016-17) :-**  
(Rs. in crore)

<b>Sr. No.</b>	<b>Year/Tranche</b>	<b>Project Sanction Target</b>	<b>Achievements</b>	<b>% age</b>
1.	2006-07 (XII)	277.00	273.48	98.73
2.	2007-08 (XIII)	298.00	299.26	100.42
3.	2008-09 (XIV)	406.00	425.12	104.71
4.	2009-10 (XV)	398.00	454.50	114.20
5.	2010-11 (XVI)	400.00 (HPC Approved) 560.00 (NABARD)	412.90	103.22
6.	2011-12 (XVII)	400.00 (HPC Approved) 540.00 (NABARD)	423.69	105.92
7.	2012-13 (XVIII)	400.00 (HPC Approved) 500.00 (NABARD)	432.16	108.04
8.	2013-14 (XIX)	475.00	496.09	104.44
9.	2014-15 (XX)	765.00	707.61	92.50
10.	2015-16 (XXI)	514.00	644.94	125.47
11.	2016-17 (XXII)	620.00 (HPC Approved) 545.00 (NABARD)	545.54	87.99

6. The Planning Department is the Nodal Department for processing the projects to NABARD for sanction and monitoring of the projects sanctioned under the RIDF programme.

#### 7. Details of RIDF review meetings held during the year 2016-17:

Sr. No	Name of the Meeting	Date and Place of meeting	Under the Chairmanship
1.	2.	3.	4.
1.	45 <sup>th</sup> HPC meeting on RIDF.	23 <sup>rd</sup> April, 2016 (Shimla)	Chief Secretary to the GoHP.
2.	46 <sup>th</sup> HPC meeting on RIDF.	29 <sup>th</sup> November, 2016 (Shimla)	Chief Secretary to the GoHP.
3.	MLAs meetings	30 <sup>th</sup> and 31 <sup>st</sup> January, 2017 (Shimla)	Hon'ble Chief Minister, Himachal Pradesh.

In addition to above mentioned meetings, bi-monthly review meetings were held in the regional office, NABARD Shimla. The representatives of implementing departments, NABARD and Planning Department attended these meetings. Scheme wise physical and financial progress of each department was reviewed and monitored in these meetings and implementing departments were advised to take corrective actions where required. Review meetings are also held at the level of concerned Administrative Secretary and HOD and at District level by the Deputy Commissioners.

#### X. 20-POINT PROGRAMME-2006 DIVISION:

The Twenty Point Programme-2006 (TPP-2006) is being implemented in the State as per the guidelines issued by Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India, from time to time.

The Twenty Point Programme is a monitoring mechanism which covers various socio-economic aspects like poverty eradication, employment, education, housing, health, agriculture, land reforms, irrigation, drinking water, protection and empowerment of weaker sections, consumer protection, environment, e-governance, etc.

The Ministry of Statistics & Programme Implementation (MOSPI) monitors the Programme / schemes covered under TPP-2006 at National level on the basis of performance report received from State Government and Central Nodal Ministries.

The restructured TPP-2006 consists of 20 points and 65 monitorable items which varies from State to State and from year to year. The performance of the States in the implementation of Twenty Point Programme-2006 was being ranked by the Government of India till 2009-10 and the ranking has been stopped thereafter.

Each monitorable item is categorized in the category of “Very Good”, “Good” and “Poor” on the basis of quarterly / yearly performance as follows:-

Sr. No.	Percentage achievement	Category
1.	2.	3.
1.	90% or more	Very Good
2.	80% to 90%	Good
3.	Below 80%	Poor

Planning Department, Himachal Pradesh has been declared as a nodal department for coordination, review, monitoring and reporting of quarterly / annual progress reports of Twenty Point Programme-2006 (TPP-2006) since 2007.

Himachal Pradesh has had an excellent track record in the implementation of Twenty Point Programme. The year-wise position of the State in respect of implementation of TPP-2006 at National level was as follows:-

Sr. No.	Year	Position / Grade of HP at National Level
1.	2.	3.
1.	2012-13	<b>“Very Good”</b> in all items except Road Construction (PMGSY) which was ranked <b>“Good”</b> (80% to 90%).
2.	2013-14	Placed in the <b>“Very Good”</b> Category
3.	2014-15	<b>“Very Good”</b> in all items except Houses Constructed - IAY and Houses constructed – EWS/LIG.
4.	2015-16	<b>“Very Good”</b> in all items except Area covered under Plantation (Public and Forest lands).

In order to inculcate the spirit of competition among the districts for the effective implementation of TPP-2006, the State Government is ranking the performance of each district. Based on the ranking, an award of Rs. 50.00 lakh, Rs. 30.00 lakh and Rs. 20.00 lakh respectively for first, second and third ranked district(s) is being given as an incentive. The incentive money is used for the various developmental works of the concerned district(s).

Based on the performance during 2015-16, three districts, viz.; Una scored 1<sup>st</sup> rank, Solan and Kangra have jointly shared 2<sup>nd</sup> rank in inter district ranking analysis of TPP. The award money of Rs. 1.00 crore has been distributed among these districts as under :-

Sr. No.	Name of District	Rank	Amount (Rs. in lakh)
1.	2.	3.	4.
1.	Una	1 <sup>st</sup>	50.00
2.	Solan	2 <sup>nd</sup>	25.00
3.	Kangra	2 <sup>nd</sup>	25.00

The State Government gives top priority for the effective implementation and achievement of TPP targets. The performance of TPP is regularly monitored at State, District and below district levels.

The District Planning, Development and 20 Point Programme Review Committees headed by the Chief Minister/Minister/MLA of all the districts review the progress of TPP in their quarterly review meetings. Deputy Commissioners / Additional Deputy Commissioners / Additional District Magistrates / District Planning Officers also review and monitor independently the progress of TPP with the concerned district level officers of the districts in the various meetings.

At the State level, the progress of TPP was reviewed in the various meetings held under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister, Chief Secretary, Additional Chief Secretary (Planning) and Adviser (Planning), HP.

All correspondence / works related to TPP and constitution of State, District and Sub-Divisional level Planning, Development and Twenty Point Programme Review Committees were discharged by the TPP Division during the year 2016-17.

**Twenty Point Programme 2016-17**  
**Achievements under TPP for the year 2016-17**  
**upto the 3<sup>rd</sup> quarter ending 31 December, 2016**

Item Code	Item Name/Sub Item Name	Unit	Annual Targets 2016-17	Cum. ach. upto December, 2016 (3 <sup>rd</sup> quarter)	% age Achievement
1	2	3	4	5	6
<b>01A</b>	<b>Employment generation under the NREG Act</b>				
01A01	No. of job cards issued	No.	NT	1173244	-
01A02	Employment generated	Mandays	NT	15631000	-
01A03	Wages given in cash	Rupees	NT	2407798000	-
<b>01B</b>	<b>National Rural Livelihood Mission (NRLM)</b>				
01B01*	Number of new and revived SHGs brought under NRLM fold during the financial year	No.	1270	856	67.40
01B02	Number of SHGs provided Revolving Fund (RF) during the financial year	No.	640	210	32.81
01E02*	Number of SHGs provided Community Investment Fund (CIF) during the financial year	No.	390	21	5.39
<b>05A</b>	<b>Food Security-Targeted Public Distribution System (TPDS)</b>				
05A02	Food Security: Targeted Public Distribution System (APL+BPL+AAY) (Other than NFSA+NFSA)	Tonnes	NT	383216	-
05B02	Food Security: Below Poverty Line (BPL)	Tonnes	NT	NA	
05D02	Food Security: Antyodaya Anna Yojana (AAY)	Tonnes	NT	NA	-
05E02	Food Grains under NFSA - Normal	Tonnes	NT	147163	
05F02	Food Grains under NFSA – Tide Over	Tonnes	NT	NA	-
	Other than NFSA	Tonnes	NT	235855	-
<b>06A</b>	<b>Rural Housing –PMAY-G</b>				
06A01*	Houses constructed	No.	4874	NR	-

Item Code	Item Name/Sub Item Name	Unit	Annual Targets 2016-17	Cum. ach. upto Dec., 2016 (3 <sup>rd</sup> quarter)	% age Achievement
1	2	3	4	5	6
<b>06B</b>	<b>EWS/LIG Houses in Urban Areas</b>				
06B01*	Houses constructed	No.	1312	NR	
07A03*	Habitations covered (Partially covered & Slipped back )	No.	1300	722	55.44
07B	Sanitation Programme in Rural Areas				
<b>08E</b>	<b>Institutional Delivery</b>				
08E01	Delivery in institutions	No.	NT	59269	-
<b>10A</b>	<b>SC Families Assisted</b>				
10A02*	(i)SC Families Assisted under SCA to SCSP and NSFDC	No.	1561	10009	641.19
<b>12A</b>	<b>Universalization of ICDS Scheme</b>				
12A01*	ICDS Blocks Operational (Cumulative)	No.	78	78	100.00
<b>12B</b>	<b>Functional Anganwadis</b>				
12B01*	Anganwadis Functional (Cumulative)	No.	18925	18925	100.00
<b>14A</b>	<b>No. of Urban poor families assisted under Seven Point Charter.</b>				
14A01*	Poor Families Assisted	No.		NR	-
<b>15A</b>	<b>Afforestation ( Public and Forest Lands)</b>				
15A01*	Area Covered under Plantation	Hectares	20728	7969	38.45
15A02*	Seedlings planted	In No.	13473000	7936488	58.90
<b>17A</b>	<b>Rural Roads –PMGSY</b>				
17A01*	Length of Road Constructed	Kilometer	500	588	117.6
<b>18B</b>	<b>Deendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana (DDUGJY)</b>				
18B01*	Villages electrified	No.	34	4	11.77
<b>18D</b>	<b>Energising pump sets</b>				
18D01*	Pumps sets energized	No.	1138	1513	132.95
<b>18E02</b>	<b>Supply of Electricity</b>				
18C02	Electricity supplied	Million units	NT	6756	-

## **XI. RAILWAY DIVISION:**

Planning Department is functioning as administrative department for railway works being executed in the State. Railway Division is carrying out all jobs related to Railway activities such as land acquisition, co-ordination, monitoring and review of rail projects, etc. During the year 2016-17, review and co-ordination meetings with various Northern Railway authorities, RVNL, Government of India, concerned department of State Government, etc. were held to sort out issues related to implementation of Railway Projects in Himachal Pradesh. Follow up actions of these meetings were taken during the year. Land Acquisition / construction works of mainly three following rail lines have been started. These lines are passing through Himachal Pradesh. The brief account of three rail lines are as follows:-

### **1. Bhanupali-Bilaspur-Beri Broad Gauge (BG) Rail Line (63.1Kms).**

The execution of Bhanupalli-Bilaspur-Beri new BG rail line is being done by Rail Vikas Nigam Limited (RVNL). The State Government has agreed the sharing pattern as per the CCEA decision. As per this decision State Government will share 25% cost of the project and land cost beyond Rs. 70 crore will be borne fully by the State Government. 25% cost will be shared by Ministry of Railways and 50% by Ministry of Finance, GoI. The cost of this project has been revised from Rs. 1046 crore to Rs. 2967 crore. The process of land acquisition has been started by SDM-cum-LAO (Rail) Bilaspur through negotiation with the land owners for the area falling in Himachal area. State Government has released its state share amounting to Rs. 10 crore to Northern Railway during 2009-10 and Rs. 12 crore was released to RVNL in 2016-17 for this rail line. This rail line is being monitored by PMO through PRAGATI.

### **2. Chandigarh-Baddi Rail Line (33.23Km).**

State Government has decided to bear 50% of the project cost in respect of this rail line. An estimate of Rs. 1672.29 crore has been sent to NR, HQ, New Delhi for approval by Northern Railway Chandigarh. The process of negotiation with land owners for out-right purchase of land has been started in Himachal Pradesh.

### **3. Nangal Talwara Broad Gauge Rail Line (83.74 Kms).**

Total length of this rail line is 83.74 Km and 62 Km track falls in Himachal Pradesh, out of which 44 km has been opened for traffic upto Amb-Andaura. Completion cost of this project is around Rs. 1,200 crore. The railway line to Amb Andaura-Chintpurni-Daulatpur Chowk (18km.) is under construction. This project will provide alternate route to J&K on its completion. PMO has accorded priority for this project and is being monitored through PRAGATI.

In addition to the above rail lines, the state Government has taken up the issue of **(i) Conversion of Pathankot-Joginder Nagar Narrow Gauge Rail Line into Broad Gauge and its further extension upto Leh-Ladakh via Mandi –Manali**



**and (ii) Construction of Ghanaulli –Baddi-Kala Amb-Paonta Sahib- Dehradun BG Rail line** with the Ministry of Railways, GoI from time to time. The State Government has been requesting GoI time and again to improve and expand the network of rail lines in the State.

To avoid delays in land acquisition the State Government has constituted Committees for negotiation with land owners for outright purchase of land for the different railway projects in the state. This step of the State Government will facilitate timely availability of land for the construction of railway projects in the state. Moreover, it will help to avoid litigation, delays in land acquisition and time and cost over run.

## **XII. EVALUATION DIVISION :-**

Evaluation Division of Planning Department is entrusted with the evaluation work of different plan schemes and projects. The objective of the evaluation is to make assessment of the implementation process, identify bottlenecks and gaps in implementation of the schemes and programmes and based on these findings, suggest remedial measures to make implementation process more effective. A Technical Advisory Committee has been constituted at State level to consider evaluation proposals of different implementing agencies.

## **XIII. MLA PRIORITY DIVISION:**

MLA Division has performed following works during the financial year 2016-17:-

- i. The minutes of MLAs meetings held during 2016-17 were issued to all the departments / organizations for taking suitable follow-up actions. The action taken report of these meetings was obtained from the concerned departments. The ATR was consolidated and circulated to all the concerned MLAs for their information.
- ii. The MLAs meetings to determine the MLAs priorities for Annual Budget 2017-18 were convened under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister HP on 30<sup>th</sup> & 31<sup>st</sup> January, 2017.
3. As per the approved policy of the State Government, Hon'ble MLAs prioritize two schemes each under three sectors i.e. **Roads & Bridges, Minor Irrigation and Rural Drinking Water Supply** for **“Really New Schemes (RNS)”** and **“Ongoing Schemes”**. Therefore, six schemes under RNS and six under Ongoing Schemes are prioritized by each MLA for every financial year. However, Hon'ble MLAs are at liberty to change inter sectoral priorities with in the above mentioned three sectors i.e. he may give six priorities in one or two or three sectors. Accordingly, the MLAs priorities were collected, consolidated and finally printed as **“नव व्यय अनुसूची के परिशिष्ट (योजना) माननीय विधायकों द्वारा निर्दिष्ट प्राथमिकताएं वर्ष 2017-18”**. It is one of the Documents for 2017-18 Budget.

4. The works related to MLAs priority are of varied nature. Various proposals for substitution of schemes were received from the various Hon'ble MLAs. Actions on the substitution proposals were taken as per approved policy. Implementing departments were asked to take the follow-up action accordingly. Concerned MLAs were also informed about the decisions taken in each substitution case.

#### **XIV. COMPUTERISATION DIVISION:**

Computerisation Division has been constituted for fulfilling the computer needs of Planning Department. All the reports / publications published by the Planning Department are processed on computer and later-on get printed on off-set in Printing Press. This division has been catering the needs of software development for the department and has developed the following softwares for different Divisions of Planning Department :-

1. Modifications/Updation of GN Software for Annual Plan 2016-17.
2. Modifications/Updation of RIDF Software.
3. Modifications/Updation of MLA Priority Schemes Software.
4. Development of State Innovation Council Software.
5. Document of Draft Annual Plan 2016-17.
6. esalary Payroll/ADA/Pay Scale Arrear of Department.
7. MLA Priority Schemes Data Entry.
8. Backward Area Sub-Plan, District/SOE-wise allocation of budget outlays.
9. Evaluation Study Reports on various Plan Programmes/Schemes.
10. Modification/Updation of Income Tax Statements Software.
11. Computerisation of Hon'ble MLAs Priority Schemes for the year 2016-2017.
12. Fact Book on Manpower Publications.
13. Power Point Presentation on various meetings in the department.
14. Twenty Point Programme Quarterly Document.
15. Development of Department Web site and site maintenance/updation.
16. Assistance to all Divisions of Department about hardware and software application.
17. Performance Management and Accountability Toolkit (PMAT).
18. e-service book of all employee of department
19. eVitran – Himkosh working
20. MIS ACA/SPA on Central Assistance (Niti Ayog).
21. MPLADs Software Monitoring.
22. Decentralized MIS Software Monitoring.
23. E-Vidhan work / Monitoring
24. Development of application for State Finance Commission.

### **3.3. DISTRICT OFFICES :**

District Planning Cells have been created in all the ten Non-Tribal districts of the State. These offices are functioning under the control of the concerned Deputy Commissioners. The Additional Deputy Commissioner / Additional District Magistrate, as the case may be, has been declared as Chief Planning Officer. The District Planning Cells are headed by the District Planning Officers. They are functioning as Drawing & Disbursing Officers at district level. The following staff has been provided in District Planning Cells :-

1. District Planning Officer.
2. Credit Planning Officer.
3. Assistant Research Officer.
4. Statistical Assistant.
5. Sr. Assistant (two posts each in District Shimla, Mandi and Kangra).
6. Steno-Typist.
7. Clerk.
8. Peon.

All the decentralized planning programmes such as VMJS, SDP, VKVNY, MMGPY, MPLADs, BASP, etc are being implemented at district level through the concerned District Planning Cell. The collection of data for evaluation studies carried out by the department are also collected through District Planning Cells at district level. District Planning Cells have been assigned the job of monitoring and reviewing of ongoing Plan Schemes, 20-Point Programme and all decentralized programmes mentioned above through District Planning, Development and Twenty Point Programme Review Committees on quarterly basis. District Planning Officers function as Public Information Officer of Planning Department at district level. District Planning Cells have proved extremely useful at district level in fulfilling the objective of decentralization of planning process of the State Government. All assignments of the department required to be undertaken at district level are performed through District Planning Cells.

#### 4. INFORMATION UNDER RTI ACT-2005:

##### Information related to the Section 4(1)(b) of the Right to Information Act.2005.

(i)	Particulars of organization, functions and duties.	Please see heading : <b>1. BACKGROUND AND INTRODUCTION and 3. ORGANISATIONAL STRUCTURE” of the report</b>
(ii)	Powers and duties of its Officers and Employees.	<p><b><u>Adviser (Planning):</u></b> Overall administrative and financial control of the Department. He helps Addl. Chief Secretary (Planning) to the GoHP in discharging various responsibilities to achieve organizational goals. Adviser (Planning) works under the overall control of Addl. Chief Secretary (Planning) to the GoHP.</p> <p><b><u>Joint Director (Planning):</u></b> He has been declared as Head of Office of Planning Department. He assisted Adviser (Planning) in discharging various responsibilities and accomplished tasks related to formulation, implementation and liaisoing with the Planning Commission, Government of India assigned to him from time to time.</p> <p><b><u>Deputy Directors:</u></b> The Deputy Directors headed various Divisions such as Plan Formulation, Plan Implementation, Project Formulation, Evaluation, Employment, Computerization, Administration, Regional and District Planning, Backward Area Sub-Plan, Twenty Point Programme, Railways, MLA Priorities, RIDF and RFD. They assisted the Adviser (Planning) in discharging various responsibilities to achieve organizational goals.</p> <p><b><u>Research Officers:</u></b> The Research Officers assist the Deputy Directors and control the staff deployed in various Divisions. All the files are routed to Deputy Directors through Research Officers.</p> <p><b><u>District Planning Officers:</u></b> The staff provided to the District Planning Officers and duties performed by them are given under heading “<b>3.3. DISTRICT OFFICES</b>”.</p> <p><b><u>Assistant Research Officers:</u></b> Deal with the various works/proposals/correspondence and submit the same with their comments to the Research Officers for taking decisions at the higher level.</p>

		<p><b><u>Statistical Assistants:</u></b> Deal with the various works / proposals / correspondence and submit the same with their comments to the Research Officers for taking decisions at the Higher level.</p> <p><b><u>Computer:</u></b> They perform their duties and functions as assigned to them by the Research Officers.</p> <p><b><u>Programmer :</u></b> The Programmer is the in-charge of the Computer Cell. He develops software as per the requirement of the department and all other computer related jobs.</p> <p><b><u>Program Planning Officers (PPOs) :</u></b> They help in developing software as per the requirement of the department and all other computer related jobs.</p> <p><b><u>Computer Operators :</u></b> They assist the Programmer/PPOs in software development, data feeding and render the computer related technical help and guidance to the department.</p> <p><b><u>Superintendent Gr.-I:</u></b> All the files of Administration Division are put-up to Superintendent Gr-I through Superintendent Gr-II with the administrative proposals for taking decisions at higher level</p> <p><b><u>Superintendent Gr.-II:</u></b> All the Senior / Junior Assistants and clerks of Administration Division submit the files through Superintendent Gr.-II. He puts up the files to Superintendent Gr.-I/ DDO / Joint Director (Administration) for final decision at appropriate level.</p> <p><b><u>Senior Assistants / Junior Assistants:</u></b> Deal with administrative, personnel, budget, organizational, etc matters and also works assigned by Superintendent / DDO / Higher Officers.</p> <p><b><u>Clerks :</u></b> Perform duties and functions as assigned to them by HOD/Superintendent Gr-I/DDO/Spud. Gr.-II including the work of diary dispatch of the Department.</p> <p><b><u>Personal Assistant / Sr. Scale Stenographer / Jr. Scale Stenographers:</u></b> Perform duties with Head of Department, Joint Directors / Deputy Directors, such as dictation / typing work / attend to the telephone calls, handle the files / records of confidential or secret nature and any other work assigned by the officer.</p>
--	--	--

		<p><b><u>Steno Typists:</u></b> Perform duties of dictation and typing work with the officers. Ten posts of Steno-Typists are sanctioned in the ten Non-Tribal Districts and they performed their duties with the District Planning Officers in the Districts.</p> <p><b><u>Duplicating Machine Operator:</u></b> To operate the Photostate machines of the Department.</p> <p><b><u>Peons:</u></b> They perform the duties as per office manual.</p> <p><b><u>Chowkidar :</u></b> Keeps watch and ward during and after office hours of all the office rooms of the department. He is also responsible for all precautionary measures relating to prevention of fire and damage to Government property.</p> <p><b><u>Sweeper:</u></b> To sweep, clean and mop the rooms, corridors, verandahs. Clean lavatories, urinals, washbasins, etc daily and properly. To collect and dispose off all waste in the office.</p>
(iii)	Procedure followed in the decision making process including channels of supervisions and accountability.	<p>Adviser (Planning) exercises all the powers of Head of Department. All the officers of the department assist him in taking decisions and disposing of the normal work of the department.</p> <p>The HOD assigns the duties to the various officers. The files move to the Adviser (Planning) through the Joint Director/ Divisional Heads for final decision/ disposal. Divisional Heads are responsible and accountable for supervision and timely disposal of work in respect of their division. (s)</p>
(iv)	Norms set by it for the discharge of its functions.	Different functions of the Department at various levels are performed in accordance with the rules / policies and delegation of powers made by the Government / HOD from time to time.
(v)	Rules, Regulations, instructions, manuals and records, held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions.	<p>The brief of Rules, Regulation, Instructions, manual held by the Department are as under:-</p> <p>CCS Leave Rules, 1972.</p> <p>CCS and CCA Rules</p> <p>HPFR Rules</p> <p>FR &amp; SR Rules</p> <p>Medical Attendance Rules</p> <p>House Building Advance Rules</p> <p>L.T.C. Rules</p>

		<p>Budget Manual Office Manual Pension Rules GPF Rules</p> <p><b>Guidelines for implementation of the following programmes:-</b></p> <p>Sectoral Decentralized Planning (SDP) Vikas Mein Jan Sahyog Program (VMJS) Vidhayak Ksehetra Vikas Nidhi Youna (VKVNY) Mukhya Mantri Gram Path Yojna (MMGPY) Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADs) Backward Area Sub Plan (BASP) Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) Externally Aided Projects (EAPs) District Innovative Fund (DIF)</p> <p>Guidelines/instructions issued by the Government from time to time are uploaded on the website of Planning Department can be used by officers and officials for discharging their functions and duties. The Administrative report containing the programmes alongwith organizational structure detail is uploaded on the website of Planning Department.</p>
(vi)	Statement of the Categories of the documents that are held by it or under its control.	Five year Plans / Annual Plans, Evaluation studies on different Plan Programmes / schemes, Fact book on Man Power & Employment, Mid Term Review of Five Year Plans. MLA Priorities Schemes document, Twenty Point Programme Quarterly District Ranking Analysis Reports and Annual Administrative Report.
(vii)	The particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof.	The State Government has constituted HP State Planning Board, State Level Planning Development Twenty Point Programme Review Committee at State level and District Planning Development and Twenty Point Programme Review Committee at District level as well as Sub-Divisional Level Planning Development, Twenty Point Programme Review and Public Grievance Committees at Sub Divisional level. Public representatives have been nominated by the State Government in these committees. Nominated public representatives give their opinion / suggestions regarding policy formulation and implementation at State, District and Sub Divisional level. Apart from this, MLAs meetings to identify the State Annual Plan

		priorities are also held. Hon'ble MLAs give their valuable suggestions regarding formulation of policies, programmes and implementation.
(viii)	A statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public.	<p>The following Boards / Committees have been constituted in the department:-</p> <p>Himachal Pradesh State Planning Board.</p> <p>State Level Planning, Development &amp; Twenty Point Program Review Committee.</p> <p>District Level Planning Development &amp; Twenty Point Program Review Committees (DPDCs) in all Districts.</p> <p>Sub-Divisional Level Planning Development, Twenty Point Programme Review &amp; Public Grievance Committees.</p> <p>Meetings of these committees/Boards are not open for public. However, public can have access to the minutes by formally applying for it.</p>
(ix)	A directory of its officers and employees;	Detail given under heading <b>“2. STAFF POSITION OF PLANNING DEPARTMENT”</b> .
(x)	The monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulations;	The Officers and the employees appointed in the Department get the Pay Band and Grade Pay as granted by the Government from time to time.
(xi)	The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made;	The Planning Department allocates funds on quarterly basis to the implementing departments and Deputy Commissioners for plan schemes and other various decentralized planning programmes according to the guidelines, formula and instructions issued by State Government from time to time. The division-wise details of goals, objectives, programmes, allocation, expenditure, etc. have been given in the write-up of the each divisions.



(xii)	The manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes;	There is no subsidy programme being executed directly by the department.
(xiii)	Particulars of recipients of concessions, permits or authorization granted by it,	Not applicable. Only Plan budget authorizations to incur an expenditure are granted by the Planning Department to all the implementing departments (concerned with Plan) and Deputy Commissioners.
(xiv)	Details in respect of the information, available to or held by it, reduced in an electronic form;	The Department has developed its own Website and the information relating to the various activities of the Department is available on the website <a href="http://hp_planning.nic.in">http://hp_planning.nic.in</a> .
(xv)	The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use.	The Public can have information from the district offices of Planning Department or its Headquarters i.e. Yojna Bhawan, HP. Sectt. Shimla-2 from 10.00 A.M to 5.00 P.M in 6 days in a week except on public holidays.
(xvi)	The names, designations and other particulars of the Public Information Officers;	Information is given below.
(xvii)	Such other information as may be prescribed; and thereafter update these publications every year.	Nil

**Particulars of the APIOs, PIOs and Appellate Authority in Planning Department, HP.**

<b>Sl. No</b>	<b>Name of Authority i.e. APIO / PIO / Appellate Authority</b>	<b>Designation</b>	<b>Address with Telephone No.</b>	<b>Jurisdiction/Unit under his control for which he will render information to applicants</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
<b>(A) SECRETARIAT LEVEL</b>				
1.	Sh. Rikhi Ram, Public Information Officer.	Deputy Secretary (Plg.) to the Govt. H.P	Armsdale Building H.P. Sectt. Shimla-2 Tel.No.2628504	Planning Department at Secretariat level.
2.	Dr. Shri Kant Baldi Appellate Authority	Addl. Chief Secretary (Planning) to the Govt. H.P.	Armsdale Building H.P. Sectt. Shimla-2. Tel. No. 2620043	Planning Department at Secretariat level.
Notification No. Plg.A(3)4/2005 dated 27-06-2009 under section 5 and 19 of “Right to Information, Act 2005” (Act No. 22 of 2005).				
<b>(B) STATE LEVEL</b>				
1.	Sh. Diwan Chand, PIO	Supdt. Gr.-I	Yojna Bhawan, H.P. Sectt. Shimla-2 Tel.No. 2629471	Planning Department at State level.
2.	Sh. Bhag Singh Thakur, APIO	Supdt. Gr.-II	Yojna Bhawan, H.P. Sectt. Shimla-2 Tel.No. 2880371	Planning Department at State level.
3.	Sh. Akshay Sood Appellate Authority	Adviser (Planning)	Yojna Bhawan, H.P. Sectt. Shimla-2 Tel.No. 2621698	Planning Department at State level.
Notification No. PLG.A(3)4/2005 dated 22-12-2005 and dated 16-04-2010 under section 5 and 19 of “Right to Information, Act 2005” .				

<b>Sr. No</b>	<b>Name of Authority i.e. APIO / PIO / Appellate Authority</b>	<b>Designation</b>	<b>Address with Telephone No.</b>	<b>Jurisdiction / Unit under his control for which he will render information to applicants</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
<b>(C) DISTRICT LEVEL</b>				
1.	Sh Tara Chand Chauhan, Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Shimla Telephone No. 0177-2808399	Concerned District.
2.	Sh. Pardeep Purta, Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Solan Telephone No. 01792- 220697	Concerned District.
3.	Sh. Anuj Kumar, Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Sirmour at Nahan Telephone No. 01702-223008	Concerned District.
4.	Sh. Gautam Chand Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Chamba. Telephone No. 01975-226057	Concerned District.
5.	Sh. Ravinder Katoch , Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Kangra at Dharamshala Telephone No. 01892-223316	Concerned District.
6.	Sh. Kuldeep Singh Minhas Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Mandi Telephone No. 01905-225212	Concerned District.
7.	Sh. Vinod Kumar Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Una Telephone No. 01899-226166	Concerned District.
8.	Smt. Mukta Thakur, Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Bilaspur Telephone No. 01978-222668	Concerned District.
9.	Sh. Tej Singh Thakur, Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Kullu Telephone No. 01902-222873	Concerned District.
10	Sh. Rajiv Kumar, Public Information Officer	District Planning Officer	District Planning Cell, DC Office Hamirpur Telephone No. 01972-222702	Concerned District.
Notification No. Plg.A(3)4/2005 dated 22-12-2005 for implementation of “Right to Information, Act 2005”.				